

# टाइडिंग्स

एनआईडीएम पत्रिका-2/2026  
जनवरी-मार्च, 2026



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान  
( गृह मंत्रालय, भारत सरकार )

वेबसाइट

<https://nidm.gov.in>



/nidmmhaindia



/nidmmhaindia



/nidmmhaindia



/nidmindia



/nidmmhaindia

## राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान संबंधी जानकारी

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) की स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत भारत और इस क्षेत्र में क्षमता विकास के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में भूमिका निभाने के दृष्टिकोण के साथ किया गया था। इस दिशा में जो प्रयास वर्ष 1995 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र (एनसीडीएम) की स्थापना के साथ शुरू हुई थी, उन्हें प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के रूप में फिर से नामित किए जाने के बाद और अधिक गति प्राप्त हुई।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रलेखन एवं पॉलिसी एडवोकेसी से संबंधित नोडल जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

एनआईडीएम ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण को राष्ट्रीय एजेंडा के केंद्र में लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संस्थान का मानना है कि सभी हितधारकों की सहभागिता से “रोकथाम की संस्कृति” को बढ़ावा देकर ही आपदा जोखिम न्यूनीकरण संभव है। एनआईडीएम केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, देश-विदेश की शैक्षणिक, अनुसंधान एवं तकनीकी संस्थाओं तथा अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से कार्य करता है।

एनआईडीएम को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के अलग-अलग पहलुओं पर कार्य करने वाले प्रोफेशनल्स की मल्टी-डिसिप्लिनरी टीम पर गर्व है। प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास को सुगम बनाने के अपने प्रयासों के अंतर्गत, संस्थान में अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जिनमें क्लास रूम, सेमिनार हॉल, वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएँ आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, संस्थान में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर एक सुव्यवस्थित और समृद्ध पुस्तकालय भी है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में एनआईडीएम विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय एजेंसियों को क्षमता निर्माण में सहयोग भी प्रदान करता है। संस्थान का दृष्टिकोण आपदा रोकथाम एवं तैयारी के लिए सभी स्तरों पर क्षमता का निर्माण कर एक आपदा-रोधी भारत का निर्माण करना है।

# NIDM

## पत्रिका

### 02/2026

## जनवरी-मार्च, 2026

# संपादकीय मंडल

**प्रधान संपादक**  
श्री मधुप व्यास, भा.प्र.से.  
कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम

**संपादक**  
डॉ. अजिंदर वालिया  
एसोसिएट प्रोफेसर

**संपादकीय सहायता**  
(डिजाइन एवं प्रस्तुति)  
सुश्री नाज़िया खान  
वरिष्ठ परामर्शदाता, सूचना एवं  
जनसंपर्क अधिकारी

**सह-संपादक**  
डॉ. रविन्द्र सिंह  
वरिष्ठ परामर्शदाता

**सहायक संपादक**  
डॉ. कुंदन देवल  
परामर्शदाता

**अनुवादक**  
संजय कुमार  
परामर्शदाता, राजभाषा

### विषय सूची

1.	संदेश	2
2.	आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम	3
3.	सम्मेलन/ कार्यशाला/ सेमिनार/ परामर्श बैठक	14
4.	अन्य संस्थागत क्रियाकलाप	22
5.	विषयगत दृष्टिकोण	28
6.	एनआईडीएम प्रकाशन	39
7.	एनआईडीएम पोर्टल्स	40

# आंतरिक विषय-वस्तु

## राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

ITEC के अंतर्गत आपदा जोखिम प्रबंधन पर 13वां समग्र पाठ्यक्रम, 16-27 फरवरी 2026, दिल्ली

5



आपदा से निपटने की तैयारी और प्रतिक्रिया विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 19-21 जनवरी 2026, आंध्र प्रदेश

9



आपदा पश्चात् आवश्यकताओं का आकलन नियमावली/ मानक संचालन प्रक्रिया के संशोधन पर कार्यशाला, 19 जनवरी 2026, दिल्ली

14



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एवं संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय के बीच रणनीतिक संवाद

24



# राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ( एनआईडीएम ) कार्यकारी निदेशक का संदेश



प्रिय पाठकों,

टाइडिंग्स के इस अंक के माध्यम से आप सभी से पुनः संवाद स्थापित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जनवरी से मार्च, 2026 की अवधि में एनआईडीएम द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में ज्ञान-विकास, संस्थागत क्षमता निर्माण तथा साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में निरंतर कार्य किया गया है। बदलते जोखिम परिदृश्य के बीच यह हमारे लिए सीखने, सुदृढ़ होने और मिलकर आगे बढ़ने का अवसर भी है।

इस अवधि के दौरान संस्थान द्वारा आपदा जोखिम प्रबंधन पर 11वें, 12वें एवं 14वें व्यापक पाठ्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इन पाठ्यक्रमों में देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों ने भाग लिया। विशेष रूप से 16-27 फरवरी 2026 के दौरान विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित 13वें व्यापक पाठ्यक्रम में 10 देशों की भागीदारी के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग और अनुभवों का आदान-प्रदान एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा। इसके अतिरिक्त विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (2025 बैच) के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

नीति समर्थन के अंतर्गत आपदा प्रबंधन योजनाओं के सुदृढ़ीकरण तथा आपदा-पश्चात् आवश्यकताओं का आकलन (PDNA) मैनुअल के संशोधन पर कार्य जारी रहा। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर आपदा-रोधी क्षमता को मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं। उच्च शिक्षा में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्यधारा में लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर दो-क्रेडिट कौशल पाठ्यक्रम को लागू करने तथा देशभर के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में डीआरआर क्लब स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की गई है।

इस अवधि में संस्थागत सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) के विशेष प्रतिनिधि श्री कमल किशोर तथा वरिष्ठ नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय विचार-विमर्श आयोजित किए गए, जिससे वैश्विक अनुभवों के आदान-प्रदान और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा मिला। साथ ही, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ मिलकर आपदा जोखिम न्यूनीकरण संग्रहालय के विकास की दिशा में कार्य किया जा रहा है, जिससे कि जन-जागरूकता और सामुदायिक तैयारी को सुदृढ़ किया जा सके।

आगे की दिशा में, वर्ष 2026-27 के दौरान एनआईडीएम अपने क्षमता निर्माण तंत्र को और सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अंतर्गत सहभागी और व्यावहारिक प्रशिक्षण दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाएगा तथा मास्टर ट्रेनर्स का एक सशक्त नेटवर्क विकसित किया जाएगा, जिससे राज्यों और संस्थानों तक व्यापक पहुँच सुनिश्चित हो सके। एनआईडीएम भारत सरकार के शैक्षणिक संस्थानों, विशेषज्ञों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर ज्ञान को व्यावहारिक में परिवर्तित करने तथा एक सुरक्षित, सक्षम और आपदा-रोधी भारत के निर्माण में अपना योगदान देता रहेगा।

सम्पुप

मधुप व्यास, भा.प्र.से.

# आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनआईडीएम नई दिल्ली कैंपस

आपदा जोखिम प्रबंधन पर 11वाँ समग्र पाठ्यक्रम 05-16 जनवरी, 2026, दिल्ली



## मुख्य बातें/अनुशासण

क)	आपदा प्रबंधन योजनाएँ (DMPs) व्यवस्थित प्रक्रियाओं के माध्यम से तैयार की जाती हैं, जिनमें HRVC आकलन और SOP-आधारित योजना शामिल है। HRVC विश्लेषण में मात्रात्मक और गुणात्मक, दोनों तरह के उपकरणों का उपयोग किया जाता है; यह मानते हुए कि जोखिम और संवेदनशीलता गतिशील तथा संदर्भ-विशिष्ट होते हैं।	होती हैं। समय पर संचार के प्रसार और प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और निर्णय लेने में सहयोग करने वाली व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।	
ख)	क्षेत्र-आधारित आकलन वास्तविक समय के खतरों, संवेदनशीलताओं और स्थानीय क्षमताओं की पहचान करके व्यावहारिक समझ को बढ़ाते हैं।	च)	विकसित प्रतिक्रिया प्रणालियाँ आपात स्थितियों के दौरान समन्वय में सुधार करती हैं, भूमिकाओं को स्पष्ट करती हैं और दक्षता बढ़ाती हैं। पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण में "Build Back Better" दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जो दीर्घकालिक विकास में प्रतिरोधक क्षमता को एकीकृत करता है।
ग)	बहु-आपदा दृष्टिकोण आवश्यक हैं, क्योंकि आपदाएँ परस्पर जुड़ी होती हैं और उनके लिए एकीकृत शमन और प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता होती है।	छ)	आपदा के प्रभावों में भौतिक क्षति और आर्थिक नुकसान, दोनों शामिल होते हैं, जिनके लिए व्यवस्थित आकलन विधियों की आवश्यकता होती है।
घ)	GIS, रिमोट सेंसिंग और डेटा उपकरणों जैसी तकनीकें जोखिम आकलन, निगरानी और जानकारी आधारित निर्णय लेने में सहायक	ज)	प्रकृति-आधारित और स्थायी दृष्टिकोण दीर्घकालिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में योगदान देते हैं।

बड़े समूह समागमों में भीड़ प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 07-09 जनवरी 2026, केरल



## मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	भीड़ से संबंधित आपात स्थितियों को भाग लेने वाली भीड़ के व्यावहारिक पहलू के रूप में देखा जाना चाहिए। इसलिए, भीड़ प्रबंधन टीम में व्यवहार विशेषज्ञ को भी शामिल किया जा सकता है।
ख)	विभिन्न पहलुओं, जैसे कि आने वाले लोगों की संख्या का रिकॉर्ड रखना, भीड़ की आवाजाही और रहने की जगहों की निगरानी करना, और गर्भगृह क्षेत्र पर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
ग)	भीड़ के बीच से ही नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों की पहचान और उनका सहयोग लेना, भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने में सहायक होता है।
घ)	प्रशासन और कार्यक्रम आयोजकों के पास इकट्ठा होने वाली भीड़ की संख्या और उनके प्रोफाइल के बारे में पहले से जानकारी

	होनी चाहिए, जिससे कि उसी के अनुसार योजना बनाई जा सके।
च)	एक आधार शिविर स्थापित किया जाना चाहिए, जहाँ मुख्य स्थल तक पहुँचने से पहले भीड़ को एकत्रित किया जा सके। इस आधार शिविर पर आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ सुनिश्चित की जानी चाहिए।
छ)	हर संबंधित पक्ष के लिए स्पष्ट भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ निर्धारित की जानी चाहिए, और जो लोग यह कार्य कर रहे हैं, उन्हें अपनी-अपनी भूमिकाओं के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
ज)	यदि संभव हो, तो गर्भगृह तक जाने वाले रास्ते में स्थित दुकानों को आधार शिविर में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जिससे कि रास्ते में लोगों का ध्यान न भटके।

## आपदा जोखिम प्रबंधन पर 12वाँ समग्र पाठ्यक्रम, 02-13 फरवरी 2026, दिल्ली



## मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	राहत-केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर, एक सक्रिय आपदा जोखिम प्रबंधन (DRM) ढांचे की ओर एक बुनियादी बदलाव की आवश्यकता है; इसके लिए सभी विकास नियोजन प्रक्रियाओं में जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत किया जाना चाहिए।
ख)	सक्रिय वित्तीय तंत्रों को संस्थागत रूप देने की अत्यंत आवश्यकता है, जिसमें समर्पित कोष और बीमा जैसे जोखिम हस्तांतरण के साधन शामिल हों, यह मानते हुए कि शमन में किया गया निवेश, आपदा के बाद की पुनर्प्राप्ति लागत को काफी हद तक कम कर देते हैं।
ग)	GIS, रिमोट सेंसिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग को बढ़ाना अनिवार्य है, जिससे कि पूर्वानुमान आधारित विश्लेषण, वास्तविक समय में निगरानी, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और संसाधनों का कुशल प्रबंधन संभव हो सके।
घ)	जोखिम न्यूनीकरण को शहरी नियोजन में व्यवस्थित रूप से एकीकृत किया जाना चाहिए; इसके लिए सुदृढ़ बुनियादी ढांचे,

	स्थायी डिजाइन (जैसे, 'स्पंज सिटी' की अवधारणाएँ) और भूमि-उपयोग संबंधी सख्त नियमों का सहारा लिया जाना चाहिए।
च)	आपदा प्रबंधन में सामुदायिक स्तर पर क्षमता निर्माण, संवेदनशील समूहों के लिए समावेशी नियोजन और जागरूकता सृजन पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए—जिसमें जोखिम हस्तांतरण तंत्रों के संबंध में वित्तीय साक्षरता भी शामिल हो।
छ)	एक 'बहु-खतरा, बहु-क्षेत्रीय' दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों (स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, वित्त, पर्यावरण) और शासन के विभिन्न स्तरों पर समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
ज)	परिचालन तत्परता सुनिश्चित करने के लिए, व्यावहारिक और अनुभव-आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से निरंतर क्षमता निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसमें केस स्टडी, क्षेत्रीय अनुभव (field exposure) और सिमुलेशन जैसी विधियाँ शामिल हों।

## ITEC के अंतर्गत आपदा जोखिम प्रबंधन पर 13वां समग्र पाठ्यक्रम, 16-27 फरवरी 2026, दिल्ली



### मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	आपदा जोखिम न्यूनीकरण के ढांचों, संस्थागत तंत्रों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की बेहतर समझ विकसित किया जाना चाहिए।
ख)	सक्रिय, जोखिम-आधारित योजना, तैयारी और प्रतिरोधक क्षमता निर्माण की दिशा में बदलाव को सुदृढ़ करना चाहिए।
ग)	आपदा प्रबंधन में भू-स्थानिक उपकरणों, रिमोट सेंसिंग और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के उपयोग को सशक्त बनाना चाहिए।

घ)	सिमुलेशन, केस स्टडी और क्षेत्र-आधारित संस्थागत अनुभव के साथ एकीकृत कक्षा सत्र आयोजित की जानी चाहिए।
च)	आपदा शासन, समन्वय तंत्र और वित्तपोषण ढांचों की समझ को सुदृढ़ करना चाहिए
छ)	ITEC में भाग लेने वाले देशों के बीच अंतर-देशीय ज्ञान आदान-प्रदान और सहयोग के लिए एक सुदृढ़ मंच तैयार किया जाना चाहिए

## उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए आपदा प्रबंधन योजना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 19-20 फरवरी 2026, दिल्ली



### मुख्य बातें/अनुशंसाएं

क)	प्रतिभागियों ने आपदा प्रबंधन की अवधारणाओं, ढांचों और आपदा प्रबंधन चक्र की व्यापक समझ प्राप्त की तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं के अंतर्गत DPIIT की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से समझा।
ख)	औद्योगिक खतरों की पहचान, जोखिम मूल्यांकन पद्धतियों (HIRA, HAZOP), और औद्योगिक इकाइयों के लिए ऑन-साइट और ऑफ-साइट आपातकालीन योजना बनाने के व्यवस्थित तरीकों में क्षमता को मजबूत किया गया।
ग)	प्रतिभागियों ने वैश्विक और राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण नीतियों की समझ विकसित की, और DPIIT की औद्योगिक नीतियों, निवेश संवर्धन गतिविधियों और क्षेत्रीय कार्यक्रमों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्यधारा में लाने के लिए ठोस उपायों की पहचान की।
घ)	व्यापार निरंतरता योजना, क्षति और हानि मूल्यांकन, और मनो-सामाजिक

	पुनर्प्राप्ति योजना में व्यावहारिक कौशल को सुदृढ़ किया गया, जिससे प्रतिभागी व्यापक संगठनात्मक प्रतिरोधक क्षमता निर्माण की रणनीति विकसित करने में सक्षम हुए।
च)	DPIIT की संस्थागत आपदा प्रबंधन योजना के प्रारूप घटकों को तैयार करने के सामूहिक अभ्यास ने प्रतिभागियों को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आपदा प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए टेम्पलेट, दिशा-निर्देश और व्यावहारिक अनुभव प्रदान किए।
छ)	प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा के लिए आपदा-रोधी औद्योगिक विकास के रणनीतिक महत्व को पहचाना, और अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के एकीकरण को बढ़ावा देने तथा भारत के औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में समग्र प्रणालीगत प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में योगदान देने का संकल्प लिया।

## जम्मू एवं कश्मीर प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों (बैच 2025) के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 23-27 फरवरी 2026, दिल्ली



### मुख्य बातें/अनुशांसाएं

क)	क्षेत्रीय प्रतिभागियों ने जम्मू और कश्मीर की विशिष्ट संवेदनशीलता का गहन विश्लेषण किया, जिसमें भूकंपीय माइक्रो-जोनेशन और बाढ़ के खतरे (GLOF) शामिल हैं; साथ ही, भविष्य के सुरक्षा उपायों को तैयार करने के लिए पारंपरिक निर्माण विधियों और भुज भूकंप जैसी पिछली आपदाओं का भी अध्ययन किया।	स्तर की तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए आपदा की स्थिति में प्रतिक्रिया तथा भीड़ प्रबंधन से जुड़े व्यावहारिक अभ्यास (सिमुलेशन) करवाए गए।	
ख)	इस कार्यक्रम ने नीति और व्यवहार के बीच एक सेतु का काम किया। इसके तहत अधिकारियों को अद्यतन 'राष्ट्रीय भवन संहिता' (NBC 2025) के बारे में जानकारी दी गई, और जमीनी	ग)	अधिकारियों को डिजिटल आपदा पोर्टल्स (जैसे 'सचेत' और IDRN) तथा राष्ट्रीय रिकवरी ढांचों के बारे में प्रशिक्षित किया गया। इस प्रशिक्षण में, लैंगिक-समावेशी आपदा प्रबंधन और भारत में जोखिम बीमा को नियंत्रित करने वाले वित्तीय तंत्रों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया।

## हिमनदीय झील के फटने से उत्पन्न बाढ़ (GLOF) के प्रति जोखिम न्यूनीकरण हेतु सामुदायिक तैयारी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 04-06 मार्च 2026, अरुणाचल प्रदेश



### मुख्य बातें/अनुशांसाएं

क)	हिमनदीय झील के फटने से उत्पन्न बाढ़ (GLOF) के जोखिम को कम करने के लिए खतरे, जोखिम और संवेदनशीलता को समझना आवश्यक है। हिमनदी झीलों, निचले इलाकों में बसी बस्तियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का वैज्ञानिक आकलन उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने और तैयारी योजना बनाने में सहायक होता है।	हैं। दुर्गम और कठिन भूभाग को देखते हुए, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, जागरूकता, तैयारी की योजना और सामुदायिक क्षमता निर्माण जैसे उपाय प्रमुख आवश्यकताएं हैं।	
ख)	अरुणाचल प्रदेश में गैर-संरचनात्मक शमन उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण	ग)	वैज्ञानिक संस्थानों के साथ सहयोग को मजबूत करना और राज्य विभागों के बीच समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करना प्रारंभिक चेतावनी प्रसार, निकासी योजना और सामुदायिक प्रतिक्रिया क्षमता में उल्लेखनीय सुधार ला सकता है।

## आपदा जोखिम प्रबंधन पर 14वाँ समग्र पाठ्यक्रम, 09-20 मार्च 2026, दिल्ली



### मुख्य बातें/अनुशांसाएं

क)	भारत में तैयारी और जोखिम को कम करने पर विशेष जोर देते हुए आपदा जोखिमों को विस्तार से बताया जाना चाहिए	घ)	तैयारी और प्रतिक्रिया प्रणालियों को बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी और सामुदायिक भागीदारी की भूमिका को मजबूत करना चाहिए।
ख)	राहत-क्रेन्द्रित दृष्टिकोण से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के एक सक्रिय ढाँचे की ओर हो रहे बदलाव को रेखांकित किया जाना चाहिए।	च)	विकास और शासन प्रक्रियाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्यधारा से जोड़ने पर बल दिया गया, जिससे सुरक्षित पुनर्प्राप्ति और स्थायी प्रतिरोधक क्षमता सुनिश्चित हो सके।
ग)	संस्थागत और सरकारी क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए।		

## ITS परिवीक्षाधीनों के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 09-13 मार्च 2026, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश



### मुख्य बातें/अनुशांसाएं

क)	भविष्य के प्रशिक्षणों में, आपदा जोखिम प्रबंधन की अवधारणाओं और दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के रूप में उनकी प्रासंगिकता की समझ को मजबूत करना चाहिए।	ख)	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण ढाँचों के बारे में समझ विकसित किया जाना चाहिए, जिसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत किए गए प्रावधान भी शामिल हों। आपदाओं के दौरान उपयोग किए जाने वाले दूरसंचार विभाग की मानक संचालन प्रक्रियाओं के बारे में बेहतर जानकारी दिए जाने की आवश्यकता है।
----	--	----	---

ग)	प्रशिक्षण के दौरान प्रदान किए गए प्रारंभिक चेतावनी और आपातकालीन संचार उपकरणों, जैसे कि कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल (CAP), प्रायोरिटी कॉल रूटिंग, IDRN, और घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (IRS) के व्यावहारिक अनुभव को प्रतिभागियों द्वारा सराहा गया।
घ)	दूरसंचार आपदा प्रबंधन योजना और प्रतिरोधक संचार प्रणालियों (Resilient Communication Systems) की बेहतर समझ विकसित की जानी चाहिए, जिसमें सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा राहत (PPDR), ERSS, और HAM रेडियो शामिल हैं।

च)	आपदाओं के दौरान संचार सहायता के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के बारे में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। ओडिशा में चक्रवातों के दौरान दूरसंचार प्रतिक्रिया से प्राप्त अनुभव पर प्रकाश डाला गया, जिसमें समन्वय और सेवाओं की त्वरित बहाली शामिल हैं।
छ)	NDRF के दौरे के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया गया, जिससे प्रतिभागियों में परिचालन प्रतिक्रिया तंत्र की समझ मजबूत हुई। सामूहिक अभ्यासों, HRVCA विश्लेषण, और NCA-T सुविधाओं के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के माध्यम से व्यावहारिक कौशल का विकास तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को सुगम बनाना चाहिए।

## समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 23-27 मार्च 2026, दिल्ली



### मुख्य बातें/अनुशासण

क)	समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन आपदा से निपटने की तैयारी, शमन, प्रतिक्रिया और पुनर्वास में प्रतिक्रिया की पहली पंक्ति के रूप में समुदायों को सशक्त बनाने पर जोर देता है।
ख)	यह कार्यक्रम आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क 2015-2030, पेरिस समझौता और संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों के सिद्धांतों को भारत की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीतियों के साथ एकीकृत करता है।
च)	जमीनी स्तर पर आपदा से निपटने की तैयारी, योजना और प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए स्थानीय प्रतिरोधक क्षमता के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

घ)	यह कार्यक्रम बढ़ते जलवायु-प्रेरित जोखिमों से निपटने के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण के साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के एकीकरण पर प्रकाश डालता है।
च)	प्रतिभागियों ने सामुदायिक तैयारी, खोज और बचाव, प्राथमिक उपचार और सामुदायिक आपदा प्रबंधन योजनाओं के विकास में व्यावहारिक कौशल प्राप्त किया।
छ)	यह प्रशिक्षण समावेशी आपदा जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा देता है, जिसमें कमजोर समूहों की भागीदारी और 'किसी को पीछे न छोड़ने' के सिद्धांत को सुनिश्चित किया जाता है, और आपदा जोखिम न्यूनीकरण को विकास कार्यक्रमों की मुख्यधारा में शामिल किया जाता है, जिससे जलवायु-रोधी और सतत् सामुदायिक विकास को मजबूती मिलती है।

# आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनआईडीएम दक्षिण परिसर

आपदा से निपटने की तैयारी और प्रतिक्रिया विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 19-21 जनवरी 2026, आंध्र प्रदेश



## मुख्य बातें/अनुशासण

क)	GIS, रिमोट सेंसिंग, AI, ड्रोन और IoT जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजी का एकीकरण आपदा से निपटने की तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास की योजना को काफी बेहतर बनाता है।	घ)	स्मार्ट डैशबोर्ड और निर्णय लेने में सहायता पहुंचाने वाली प्रणालियाँ आपातकालीन अभियानों के दौरान स्थिति की जानकारी और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को बेहतर बनाती हैं।
ख)	डेटा-आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ समय पर पूर्वानुमान और अलर्ट जारी करने में मदद करती हैं, जिससे पहले से की गई तैयारी और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की योजना के माध्यम से आपदा के असर को कम किया जा सकता है।	च)	आपदाओं के दौरान वास्तविक समय में जानकारी के आदान-प्रदान, लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने और भ्रामक सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए डिजिटल संचार और सोशल मीडिया इंटेलिजेंस बहुत जरूरी हैं।
ग)	जियो-स्पेशियल टूल्स और स्थानिक विश्लेषण (spatial analytics) जिला और राज्य स्तर पर खतरों की मैपिंग, संवेदनशीलता का आकलन और सोच-समझकर फैसले लेने में मदद करते हैं। ड्रोन और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी नुकसान का तेजी से आकलन करने, खोज और बचाव कार्यों में, और आपदा से प्रभावित उन इलाकों की निगरानी करने में अहम भूमिका निभाते हैं जहाँ पहुंचना मुश्किल होता है।	छ)	आपदा जोखिम के प्रभावी प्रबंधन और तैयारी व बचाव की रणनीतियों को लागू करने के लिए मजबूत संस्थागत तालमेल और कानूनी ढाँचे का होना बहुत जरूरी है।

भारत में टिड्डियों के प्रकोप से बचने के लिए आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 28-30 जनवरी 2026, आंध्र प्रदेश



## मुख्य बातें/अनुशासण

क)	इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिभागियों को यह स्पष्ट हो गया कि टिड्डियों का हमला केवल कृषि से जुड़ी समस्या नहीं है, बल्कि यह एक बहुआयामी आपदा है जो खाद्य सुरक्षा, आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती है; इसलिए इसे आपदा जोखिम प्रबंधन के ढांचों में शामिल किया जाना आवश्यक है।
ख)	इस कार्यक्रम ने प्रतिभागियों के टिड्डियों की जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी, प्रजनन के तरीकों, प्रवास के व्यवहार और जलवायु परिवर्तनशीलता तथा बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों से जुड़े प्रकोप के कारणों के बारे में समझ को और सुदृढ़ किया।

ग)	विभिन्न सत्रों में फसलों और आजीविका को होने वाले संभावित नुकसान को कम करने के लिए निगरानी तंत्र, पूर्वानुमान प्रणाली, उपग्रह निगरानी, ड्रोन-आधारित सर्वेक्षण और समय पर प्रारंभिक चेतावनियों के प्रसार के महत्व पर जोर दिया गया।
घ)	समूह अभ्यासों और सिमुलेशन (मॉक ड्रिल) ने प्रतिभागियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जिला-स्तरीय टिड्डी रूपी आपदा से निपटने की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए कार्य योजनाएँ तैयार करने में सक्षम बनाया।

## केरल की ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के एकीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 28-31 जनवरी 2026, केरल



## मुख्य बातें/अनुशासण

क)	इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिभागियों को आपदा प्रबंधन चक्र और कानूनी-संस्थागत ढांचे की एक व्यवस्थित समझ मिली, जिसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और संबंधित राज्य के दिशा-निर्देशों के तहत ग्राम पंचायतों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से बताया गया।
ख)	इस पाठ्यक्रम ने HRVCA (खतरा, जोखिम और संवेदनशीलता आकलन) करने, जोखिम मानचित्र तैयार करने, और पहचाने गए खतरों एवं संवेदनशीलताओं को ठोस शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया कार्यों से जोड़ने की उनकी क्षमता को मजबूत किया; इसमें प्रकृति-आधारित समाधान और GPDP के माध्यम से क्षेत्रीय निवेश भी शामिल हैं।
ग)	आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी केंद्र और ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समितियां (VHSNC) जैसी अग्रिम पंक्ति की प्रणालियों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण में स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक

	सुरक्षा को एकीकृत करने के लिए कमजोर समूहों के लिए विशेष रूप से मुख्य स्तंभों के रूप में मान्यता दी गई।
घ)	प्रतिभागियों को प्रारंभिक चेतावनी प्रसार, राहत शिविर प्रबंधन, मनोसामाजिक देखभाल और स्वयंसेवकों को जोड़ने के लिए व्यावहारिक उपकरणों से परिचित कराया गया, और उन्होंने केस स्टडी, सिमुलेशन और समूह कार्य के माध्यम से इनका उपयोग करने का अभ्यास किया।
च)	पंचायत स्तर की आपदा प्रबंधन योजनाएँ और गाँव की आपदा प्रबंधन योजनाओं के तत्वों की व्यावहारिक तैयारी, संकाय दल के मार्गदर्शन में की गई। इससे प्रतिभागियों को अपने क्षेत्रों में इसी तरह की योजना प्रक्रियाओं को दोहराने और नियमित विकास योजनाओं में शमन को मुख्यधारा में शामिल करने का आत्मविश्वास पैदा हुआ।

## समुदाय-आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन (CBDRM) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 09-13 फरवरी 2026, आंध्र प्रदेश



### मुख्य बातें/अनुशांसाएं

क)	इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में समुदाय-आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन की सहभागी और समावेशी प्रकृति पर गहराई से चर्चा की गई, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि समुदाय ही आपदा के सबसे पहले शिकार होते हैं, लेकिन वे ही सबसे पहले मदद के लिए आगे आने वाले (First Responders) भी होते हैं; इसलिए उन्हें योजना बनाने, निर्णय लेने और उसे लागू करने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए। इसमें 'किसी को भी पीछे न छोड़ने' (Leaving No One Behind) पर विशेष जोर दिया गया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आपदा से निपटने की तैयारी और प्रतिक्रिया के ढांचों में कमजोर वर्गों को भी पूरी तरह से शामिल किया जाए।	योजना बनाने, भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से तय करने, तथा योजनाओं की नियमित समीक्षा और उन्हें अद्यतन करने के महत्व को रेखांकित किया गया।
ग)	आपदा के प्रभावों को कम करने में प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, प्रभावी संचार रणनीतियों, निकासी की योजना बनाने और विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका समुदाय-आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन का एक अनिवार्य हिस्सा है। दीर्घकालिक प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए निरंतर क्षमता निर्माण, जागरूकता पैदा करना और 'मॉक ड्रिल' (अभ्यास) को प्रमुख तत्वों के रूप में पहचाना गया।	घ)
ख)	इसमें व्यावहारिक कौशल और HRVC विश्लेषण, तथा गाँव और संस्थागत आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने के लिए व्यावहारिक अभ्यास कराया गया। इस प्रशिक्षण में व्यवस्थित	विजयवाड़ा में बुडामेरू नदी का क्षेत्र-दौरा करने से इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाली व्यापक बाढ़ की घटनाओं के बारे में गहरी समझ और जानकारी प्राप्त हुई।

## आपदा पश्चात् पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 23-25 फरवरी 2026, आंध्र प्रदेश



## मुख्य बातें/अनुशांसाएं

क)	आपदा प्रबंधन चक्र- तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति और शमन की व्यापक समझ की आवश्यकता, प्रभावी आपदा जोखिम प्रबंधन और सुदृढ़ पुनर्वास योजना के लिए आधार प्रदान करती है।
ख)	भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ढाँचे के अंतर्गत, NDMA, NIDM, SDMAAs और जिला प्रशासन जैसी संस्थाओं की आपदा की स्थिति में प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति और क्षमता-निर्माण के प्रयासों के समन्वय में निभाई जाने वाली भूमिका को रेखांकित किया जाना आवश्यक है।
ग)	आपदा पश्चात् आवश्यकताओं का आकलन (PDNA) नुकसान का आकलन करने, आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाने और विभिन्न क्षेत्रों में पुनर्वास की जरूरतों की पहचान करने के लिए एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली प्रदान करता है, जिससे कि साक्ष्य-आधारित पुनर्वास योजना को बल मिल सके।
घ)	सतत पुनर्वास ढांचे इस बात पर जोर देते हैं कि बुनियादी ढांचे, आजीविका और संस्थानों को इस तरह से पुनर्निर्मित किया जाए कि दीर्घकालिक प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो, न कि पहले की कमियों को आपदा आने पर फिर से दोहराया जाए।

च)	आपदा जोखिम न्यूनीकरण, शमन और तैयारी की रणनीतियों को मजबूत करना, जलवायु-प्रेरित खतरों जैसे चक्रवात, बाढ़, लू और चरम मौसम की घटनाओं से बढ़ते जोखिमों से निपटने के लिए आवश्यक है।
छ)	क्षेत्र-वार नुकसान और क्षति आकलन कार्यप्रणालियां सरकारों को संरचित डेटा संग्रह और विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करके कृषि, आवास, बुनियादी ढांचे और आजीविका पर आपदा के प्रभावों को मापने में सक्षम बनाती हैं।
ज)	प्रभावित क्षेत्रों में क्षेत्र-आधारित शिक्षा प्रणाली, आपदा के बाद पुनर्निर्माण की चुनौतियों, सामुदायिक पुनर्वास की गतिशीलता और कार्यान्वयन में कमियों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
ट)	'बिल्ड बैक बेटर' (BBB) सिद्धांत ऐसे पुनर्निर्माण को बढ़ावा देता है जो प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के डिजाइन, बेहतर मानकों और दीर्घकालिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों को एकीकृत करता है।

## सक्रिय आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए आपदा जोखिम वित्तपोषण, आपदा पश्चात् आवश्यकताओं का आकलन और वित्तपोषण तंत्र पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 16-18 मार्च 2026, आंध्र प्रदेश



## मुख्य बातें/अनुशांसाएं

क)	भविष्य की परियोजनाओं और कार्यक्रमों में जोखिम तथा वित्तीय विश्लेषण के आधार के रूप में आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन चक्र, भारत की बहु-आयामी खतरों के प्रति संवेदनशीलता और संस्थागत ढांचे की वैचारिक समझ को सुदृढ़ किया गया।
ख)	इस प्रशिक्षण के माध्यम से HRVCA उपकरणों और क्षेत्र विशेष के प्रभाव विश्लेषण का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ, इसके तहत जोखिम संबंधी जानकारी को प्रमुख क्षेत्रों में योजना, प्राथमिकता निर्धारण और निवेश निर्णयों से जोड़ा गया। प्रतिभागियों ने इस व्यावहारिक प्रशिक्षण की सराहना की।

ग)	इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा भारत में आपदा जोखिम वित्तपोषण की संरचना के संबंध में स्पष्टता विकसित की गई, जिसमें बजटीय साधन, वित्त आयोग के प्रावधान, तथा राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर SDRF/NDRF की रूपरेखा एवं अनुप्रयोग शामिल हैं।
घ)	इस प्रशिक्षण ने हितधारकों के लिए PDNA ढांचे और PDNA की मानक संचालन प्रक्रियाओं की व्यावहारिक समझ विकसित की।

च)	इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्षति, नुकसान और पुनर्वास की जरूरतों को समझने और पुनर्प्राप्ति तथा पुनर्निर्माण में 'बिल्ड बैक बेटर' सिद्धांतों को शामिल करने पर जोर दिया गया।
छ)	केरल के PDNA और आपदा जोखिम शासन के अनुभव से परिचालन संबंधी जानकारी मिली, और उत्पादक तथा बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय क्षति और नुकसान के आकलन का अभ्यास कराया गया। यह बताया गया कि GIS/RS उपकरण और

	क्षेत्रीय PDNA टेम्पलेट मिलकर वित्तपोषण निर्णयों को सूचित करते हैं और आपदा प्रबंधन योजनाओं में वित्तीय मजबूती को शामिल करने में मदद करते हैं।
ज)	इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के दिशा-निर्देश, तथा SDRF और NDRF के मानदंड किस प्रकार कार्य करते हैं, इसकी जानकारी दी गई।

## सूखा प्रबंधन और शमन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 25-27 मार्च 2026, आंध्र प्रदेश



### मुख्य बातें/अनुशासण

क)	इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिभागियों ने सूखे की प्रभावी निगरानी के लिए SPI, NDVI जैसे प्रमुख वैज्ञानिक सूचकांकों और 'सूखा नियमावली 2016' (Drought Manual 2016) के तहत अनिवार्य अन्य मापदंडों की व्याख्या करना सीखा।
ख)	इस कार्यक्रम ने प्रतिभागियों की, सूखे की घोषणा की व्यवस्थित और समय-सीमा वाली प्रक्रिया को लागू करने की क्षमता को बढ़ाया; इसमें अनिवार्य संकेतक, प्रभाव संकेतक और क्षेत्रीय सत्यापन शामिल थे।
ग)	प्रतिभागियों ने सूखे की स्थिति के दौरान जल आपूर्ति, चारे की उपलब्धता और पशुधन की सुरक्षा के लिए 'संकट प्रबंधन योजनाएँ' (Crisis Management Plans) बनाने की जानकारी प्राप्त की।
घ)	इस प्रशिक्षण ने प्रतिभागियों को ऐसी कुशलता प्रदान की, जिससे वे वैज्ञानिक रूप से सत्यापित ज्ञापन तैयार कर सकें, जो सरकारी

	आपदा प्रतिक्रिया कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।
च)	प्रतिभागियों को सूखे से राहत और उसके प्रभाव को कम करने के प्रयासों में सहायता हेतु 'राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष' (SDRF) और 'राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष' (NDRF) तक पहुँचने की प्रक्रियाओं से परिचित कराया गया।
छ)	इस कार्यक्रम ने सूखे की बेहतर निगरानी और प्रबंधन के लिए रिमोट सेंसिंग उपकरणों, निर्णय सहायता प्रणालियों और राष्ट्रीय डेटा प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रकाश डाला।
ज)	प्रतिभागियों ने जिला-स्तरीय कार्य योजनाएँ बनाना सीखा, जिनका मुख्य जोर सूखे के दीर्घकालिक शमन, जल संसाधन प्रबंधन और सामुदायिक प्रतिरोधक क्षमता पर था।

# सम्मेलन/कार्यशाला/सेमिनार/परामर्श बैठक

परिवहन आपातकालीन प्रबंधन योजना (TEMP) और यातायात निकासी योजना (TEP) की रूपरेखा पर परामर्श कार्यशाला, 14 जनवरी 2026, दिल्ली



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा 14 जनवरी 2025 को, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से चलाए जा रहे प्रोजेक्ट- 'राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु जलवायु अनुकूलन नीति एवं दिशा-निर्देशों का विकास' (HighCAP) के तहत, परिवहन आपातकालीन प्रबंधन योजना (TEMP) और यातायात निकासी योजना (TEP) के फ्रेमवर्क पर एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में CDRI, NHA, CRR, IITs, NITs, SPA, DTU, SDMA और अन्य सरकारी व तकनीकी एजेंसियों सहित प्रमुख संस्थानों और संगठनों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य बढ़ते जलवायु जोखिमों के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए परिवहन संबंधी आपातकालीन तैयारियों और प्रतिक्रिया को मजबूत करने पर विचार-विमर्श करना था।

NH-3 (कुल्लू-मनाली) कॉरिडोर को एक केस स्टडी के रूप में उपयोग करते हुए, चर्चाओं का मुख्य केंद्र TEMP को संस्थागत समन्वय के लिए एक रणनीतिक, नीति-स्तरीय फ्रेमवर्क के रूप में विकसित करना; और TEP को

आपदाओं के दौरान कुशल निकासी के लिए एक परिचालन उपकरण के रूप में तैयार करना था। प्रतिभागियों ने परिदृश्य-आधारित योजना, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के एकीकरण, GIS और रीयल-टाइम तकनीकों के उपयोग, तथा वैकल्पिक मार्गों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

कार्यशाला में आपातकालीन प्रबंधन के दृष्टिकोण को प्रतिक्रियात्मक से बदलकर सक्रिय, जोखिम के प्रति जागरूक और प्रौद्योगिकी-सक्षम बनाने पर जोर दिया गया, जिसमें विभिन्न एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय और जीवन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना शामिल है। कार्यशाला के दौरान दिए गए सुझाव TEMP-TEP फ्रेमवर्क को और अधिक परिष्कृत करने में सहायक होंगे, तथा पूरे भारत में प्रतिरोधी और अनुकूलन-सक्षम राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणालियों के निर्माण में योगदान देंगे।

## आपदा पश्चात् आवश्यकताओं का आकलन नियमावली/ मानक संचालन प्रक्रिया के संशोधन पर कार्यशाला, 19 जनवरी 2026, दिल्ली



आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न हितधारकों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से, 'आपदा-पश्चात् आवश्यकताओं का आकलन' (PDNA) नियमावली/मानक संचालन प्रक्रिया के संशोधन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के वरिष्ठ अधिकारियों

और प्रतिनिधिमंडलों, जिनमें NDMA के सदस्य और संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन) के साथ-साथ संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों और क्षेत्र-विशेषज्ञों ने भाग लिया।

इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य डेटा प्रारूपों के सरलीकरण और मानकीकरण, PDNA नियमावली के प्रासंगिक संशोधन, तथा क्षेत्र-वार दिशा-निर्देशों और चेकलिस्ट से युक्त एक व्यावहारिक पुस्तिका के विकास के माध्यम से PDNA ढांचे को सुदृढ़ बनाना था। चर्चाओं के दौरान PDNA रिपोर्ट को समय पर प्रस्तुत करने, मानकीकृत क्षेत्रीय आकलन पद्धतियों को विकसित करने, और अधिकारियों व विशेषज्ञों के नियमित प्रशिक्षण (ओरिएंटेशन) के माध्यम से

क्षमता निर्माण करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। चर्चाओं में आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा और संवेदनशील समूहों पर पड़ने वाले प्रभावों को दर्ज करने के महत्व को भी रेखांकित किया गया; साथ ही, PDNA प्रक्रियाओं की व्यापकता और निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु अंतर-राज्यीय सूचना-आदान-प्रदान के तंत्र स्थापित करने और PDNA विशेषज्ञों का एक समर्पित संवर्ग (कैडर) तैयार करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया।

## पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) की आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में सहायता प्रदान करने के लिए प्रारंभिक-सह-परामर्श बैठक, 28 जनवरी 2026, दिल्ली



पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) की आपदा प्रबंधन योजना के प्रस्तावित ढांचे को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से दिनांक 28 जनवरी 2026 को एक प्रारंभिक-सह-परामर्श बैठक आयोजित की गई। यह बैठक श्री मधुप व्यास, भा.प्र.से., कार्यकारी निदेशक, NIDM की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि आपदा प्रबंधन योजना को 2015 के वैश्विक ढांचों, सेंडाई फ्रेमवर्क, SDGs और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। उन्होंने सभी से एक एकीकृत दृष्टिकोण के साथ काम करने का आग्रह किया, और अलग-अलग काम करने के बजाय आपस में समन्वय स्थापित कर पत्तन, पोत परिवहन के लिए एक सुदृढ़ और समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने को कहा।

श्री रणदीप कुमार राणा, वरिष्ठ सलाहकार, NIDM ने इस बात पर जोर दिया कि आपदा प्रबंधन योजना को कार्य-उन्मुख बनाया जाना चाहिए और संबंधित एजेंसियों को 'गोल्डन आवर्स' (शुरुआती महत्वपूर्ण घंटों) के दौरान पूरी दक्षता के साथ काम करना चाहिए। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में कैप्टन

आर. पोसवाल, DDG (तकनीकी), MoPSW और कैप्टन हरिंदर सिंह, DDG (तकनीकी), MoPSW उपस्थित थे। उन्होंने बंदरगाहों के आसपास होने वाली समुद्री दुर्घटनाओं और आपात स्थितियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए तैयारियों और आपसी समन्वय को मजबूत बनाने के महत्व पर जोर दिया।

इस बैठक में कुल 44 प्रतिनिधियों और विभिन्न हितधारक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें विभिन्न मंत्रालय, सरकारी विभाग, बंदरगाह प्राधिकरण, शैक्षणिक संस्थान और निजी संस्थान शामिल थे।

चर्चा के दौरान, प्रतिनिधियों और प्रतिभागियों ने बेहतर हितधारक समन्वय, व्यापक जोखिम मूल्यांकन, उभरते हुए समुद्री खतरों को शामिल करने, तथा बेहतर प्रशिक्षण और तैयारियों के माध्यम से आपदा प्रबंधन योजना को और अधिक सुदृढ़ बनाने के संबंध में बहुमूल्य सुझाव दिए। चर्चाओं में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि MoPSW के लिए एक स्पष्ट, संक्षिप्त और कार्य-उन्मुख आपदा प्रबंधन योजना का होना अत्यंत आवश्यक है, जो बंदरगाहों और समुद्री बुनियादी ढांचे से जुड़े परिचालन, पर्यावरणीय और सुरक्षा संबंधी सभी प्रकार के जोखिमों को प्रभावी ढंग से समाहित कर सके।

## आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन (SBC) को संस्थागत बनाने पर प्रसार कार्यशाला, 03 फरवरी 2026, दिल्ली



इस कार्यशाला का आयोजन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (UNICEF) द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) के सहयोग से किया गया था। इस कार्यशाला में व्यवहार-केंद्रित संदेशों और जनसंपर्क के लिए NIDM SBC-DRR टूलकिट (प्रशिक्षण सामग्री, संचार सामग्री, निगरानी चेकलिस्ट, iGOT और NIDM SBC जैसे ई-प्रशिक्षण संसाधन) के उपयोग से अवगत कराया गया। यह कार्यशाला मानवीय सहायता के क्षेत्र में सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन सिद्धांतों की समझ और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रति उनकी प्रासंगिकता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक कदम है। इसमें सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन के संस्थागत और सामुदायिक जुड़ाव में मानवीय सहायता की भूमिका पर चर्चा की गई और उसे सरिखित किया गया। यह मानवीय

सहायता एजेंसियों को अपने कार्यक्रमों के लिए एक समावेशी, जन-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण संचार और जुड़ाव रणनीति तैयार करने और उसे एकीकृत करने में सक्षम बनाता है। इस कार्यशाला ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन उपकरणों के व्यावहारिक अनुप्रयोग का अवसर प्रदान किया, आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमों में सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन की समझ को बढ़ाया, सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन के संस्थागत बनाने में मानवीय एजेंसियों की भूमिका को और स्पष्ट किया, तथा समावेशी और जन-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण संचार रणनीतियाँ तैयार करने की क्षमता विकसित की।

## सुदृढ़ राजमार्गों के लिए जलवायु-अनुकूल विकल्पों के लागत-लाभ विश्लेषण पर परामर्श कार्यशाला, 04 फरवरी 2026, दिल्ली



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) द्वारा 4 फरवरी 2026 को, 'राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु जलवायु अनुकूलन नीति एवं दिशा-निर्देशों का विकास' (HighCAP) परियोजना के तहत, सुदृढ़ राजमार्गों के लिए जलवायु-अनुकूल विकल्पों के लागत-लाभ विश्लेषण (CBA) पर एक परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। इस परियोजना को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) का सहयोग प्राप्त है। इस कार्यशाला में IITs, IISc, NITs, SPA, CRRRI, BHU, IRC, PWD, NHIDCL, MoRTH और अन्य तकनीकी तथा नीतिगत संगठनों सहित प्रमुख संस्थानों और सरकारी एजेंसियों के विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिससे कि राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जलवायु-रोधी उपायों की आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार-विमर्श किया जा सके।

NH-3 (ऑट-मनाली) कॉरिडोर पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए, अपनाए गए CBA ढांचे में जलवायु जोखिम मूल्यांकन, अनुकूलन उपायों की पहचान, वर्तमान परिस्थितियों में आर्थिक नुकसान का परिमाणीकरण, प्रतिरोधक क्षमता के निर्माण में किए गए निवेश से होने वाले लाभों का अनुमान और नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV), निवेश पर रिटर्न (ROI) तथा पेबैक अवधि जैसे संकेतकों के माध्यम

से वित्तीय मूल्यांकन शामिल है। प्रदर्शित अनुकूलन उपायों में संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों का संतुलित मिश्रण शामिल था, जैसे कि ढलान स्थिरीकरण, बेहतर जल निकासी व्यवस्था, मजबूत फुटपाथ और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ; ये उपाय क्षति, व्यवधान और मरम्मत की लागत को कम करके दीर्घकालिक आर्थिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। चर्चाओं में जीवन-चक्र लागत के महत्व, वित्तीय और आर्थिक संकेतकों के एकीकरण, तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में सामाजिक, पर्यावरणीय और अप्रत्यक्ष प्रभावों को शामिल करने पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने इस ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, वैकल्पिक मार्ग लागतों, डेटा पारदर्शिता और जलवायु जोखिम अनुमानों को शामिल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

इस कार्यशाला ने सक्रिय, साक्ष्य-आधारित और स्थायित्व-केंद्रित बुनियादी ढांचा नियोजन की ओर हो रहे बदलाव को और अधिक बल प्रदान किया है; एक ऐसा नियोजन जिसमें निवेश संबंधी निर्णय, मात्रात्मक लाभों और टाले जा सकने वाले नुकसानों द्वारा निर्देशित होते हैं।

# सूखा नियमावली संशोधन-2020 और शीत लहर, ओलावृष्टि तथा कीट के प्रकोप पर दिशा-निर्देशों के निर्माण हेतु निगरानी, पूर्वानुमान और घोषणा तंत्र पर तकनीकी परामर्श कार्यशाला, 22 जनवरी 2026, दिल्ली



भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से, 22 जनवरी 2026 को NIDM, नई दिल्ली में एक तकनीकी परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का आयोजन सूखा नियमावली-2020 के चल रहे संशोधन और शीत लहर/पाला, ओलावृष्टि तथा कीट हमले पर व्यापक दिशा-निर्देशों के निर्माण के हिस्से के रूप में पूर्वानुमान, निगरानी, प्रारंभिक चेतावनी और घोषणा तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया था।

इस कार्यशाला में नीति-निर्माता, वरिष्ठ वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ और प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिससे कि विज्ञान-आधारित, प्रभाव-केंद्रित और कृषि-संबेदनशील आपदा जोखिम मूल्यांकन ढांचों में सुधार पर विचार-विमर्श किया जा सके। इस परामर्श का उद्देश्य एक एकीकृत आपदा जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण के अंतर्गत मौसम संबंधी पूर्वानुमान, जल विज्ञान संबंधी निगरानी, कीट निगरानी और कृषि परामर्शों को आपस में समन्वित करना था।

कार्यशाला की कार्यवाही की शुरुआत एक संदर्भ-निर्धारण सत्र से हुई, जिसमें तकनीकी संकेतकों को ज़मीनी वास्तविकताओं और राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन ढांचों के साथ सामंजस्य बिटाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। श्री मधुप व्यास (भा.प्र.से.), कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम ने कृषि नियोजन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के सिद्धांतों को मुख्यधारा में लाने पर जोर दिया, जिसमें विशेष रूप से कृषि क्षेत्र को प्रभावित करने वाली जलवायु परिवर्तनशीलता और मिश्रित आपदाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के महानिदेशक, डॉ. मृत्युंजय महापात्र ने मौसम और जलवायु पूर्वानुमान के क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें अल्पकालिक, मध्यमकालिक और मौसमी-श्रेणी की पूर्वानुमान

प्रणालियों में हुए सुधार भी शामिल थे। केन्द्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) के सदस्य, श्री टी.बी.एन. सिंह ने सूखा मूल्यांकन और घोषणा प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने में भूजल संकेतकों और जल विज्ञान संबंधी मापदंडों के महत्व को रेखांकित किया।

तकनीकी विचार-विमर्श सूखा घोषणा ढांचों, विभिन्न सूचकांकों के सामंजस्य, डेटा-साझाकरण प्रोटोकॉल और निर्णय-निर्माण प्रणालियों में मौसमी तथा उप-मौसमी पूर्वानुमानों के एकीकरण पर केंद्रित रहे। प्रतिभागियों ने शीत लहर, पाला, ओलावृष्टि और कीट हमलों के लिए निगरानी ढांचों तथा घोषणा मानदंडों की समीक्षा की; साथ ही, समय पर और लक्षित हस्तक्षेप सुनिश्चित करने हेतु प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान और फसल तथा क्षेत्र-विशिष्ट सीमा-मानों (thresholds) के विकास की वकालत की। IMD, MNCFC, CRIDA, SAC-ISRO, CGWB, CWC और अन्य तकनीकी संस्थानों के विशेषज्ञों ने रिमोट सेंसिंग, कृषि-मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षकों, जल विज्ञान डेटासेट और कीट निगरानी प्रणालियों को एक एकीकृत कृषि जोखिम प्रबंधन ढांचे में शामिल करने पर हुई चर्चाओं में योगदान दिया। इस दौरान, परस्पर-संचालित डेटा प्लेटफॉर्म, रीयल-टाइम विश्लेषण और विभिन्न संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया।

इस कार्यशाला का समापन इस आम सहमति के साथ हुआ कि तकनीकी चर्चाओं को ऐसे व्यावहारिक सुझावों में बदला जाए, जिनका उपयोग 'सूखा नियमावली-2020' (Drought Manual-2020) में संशोधन करने तथा शीत लहरों, ओलावृष्टि और कीटों के हमलों से निपटने के लिए मजबूत, वैज्ञानिक आधार वाली और लागू करने योग्य दिशा-निर्देश तैयार करने में किया जा सके। इस परामर्श सत्र ने जलवायु-जनित खतरों के विरुद्ध कृषि की सहनशीलता को सुदृढ़ बनाने के लिए एक व्यापक, प्रभाव-आधारित और किसान-केंद्रित ढांचा तैयार करने की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया।

# सूखा नियमावली संशोधन-2020 और ओलावृष्टि, शीत लहर/पाला तथा कीट प्रकोप पर दिशा-निर्देशों के निर्माण हेतु क्षेत्रीय (पूर्वोत्तर और ओडिशा) हितधारक परामर्श कार्यशाला, 17 फरवरी 2026, असम



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से, 17 फरवरी 2026 को असम कृषि विश्वविद्यालय, काहिकुची परिसर, असम में एक क्षेत्रीय हितधारक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला सूखा नियमावली-2020 के संशोधन और ओलावृष्टि, शीत लहर/पाला तथा कीट प्रकोप पर व्यापक दिशा-निर्देशों के निर्माण हेतु चल रही राष्ट्रीय परामर्श प्रक्रिया का एक हिस्सा थी, जिसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों और ओडिशा पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

इस परामर्श में 71 प्रगतिशील किसानों के साथ-साथ राज्य सरकार के अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों, कृषि-मौसम विज्ञानियों, कीट विज्ञानियों, फसल विशेषज्ञों, आपदा प्रबंधन पेशेवरों और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और ओडिशा के प्रतिनिधि शामिल थे, जिससे विभिन्न कृषि-जलवायु परिस्थितियों जैसे पहाड़ी, बाढ़ प्रभावित और वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों के अनुभवों को चर्चा में शामिल किया जा सका।

कार्यशाला में तकनीकी और सहभागी सत्र आयोजित किए गए, जिनमें जमीनी स्तर पर सूखे की चुनौतियों और नमी की कमी, शीत लहर और तापमान में बदलाव के प्रभावों, फसल उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कीट और टिड्डा हमलों, तथा ओलावृष्टि से होने वाले फसलों के नुकसान पर ध्यान केंद्रित किया गया। विशेषज्ञों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में जलवायु परिवर्तनशीलता की बढ़ती आवृत्ति, छोटे और सीमांत किसानों की संवेदनशीलता, तथा स्थानीय सलाहकारी प्रणालियों और संस्थागत तैयारी को मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

किसानों ने विलंबित वर्षा, असामयिक ठंड, कीटों के प्रकोप और ओलावृष्टि के बाद की बहाली से संबंधित अपने वास्तविक अनुभवों को सक्रिय रूप से साझा किया। चर्चाओं में समय पर और कार्रवाई योग्य परामर्शों, फसल बीमा और मुआवजे की प्रक्रियाओं को सरल बनाने, प्रारंभिक चेतावनियों के अंतिम-स्तर तक प्रसार को बेहतर बनाने, तथा कृषि, मौसम विज्ञान और आपदा प्रबंधन विभागों के बीच मजबूत समन्वय स्थापित करने के महत्व पर जोर दिया गया।

इस परामर्श से कई कार्रवाई योग्य सिफारिशें सामने आईं, जिनमें जमीनी स्तर पर 'प्रारंभिक चेतावनी से प्रारंभिक कार्रवाई' (EW-EA) प्रणालियों को मजबूत करना; पूर्वोत्तर राज्यों और ओडिशा के अनुरूप विशिष्ट फसलों और क्षेत्रों के लिए विशेष परामर्श विकसित करना; समुदाय-आधारित कीट निगरानी और प्रतिक्रिया तंत्र को बढ़ाना; तथा वैज्ञानिक और प्रभाव-आधारित मूल्यांकन पद्धतियों में सुधार करना और नीति निर्माण में किसानों के अनुभवों तथा स्थानीय ज्ञान प्रणालियों को समाहित करना शामिल है।

काहिकुची में आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला ने विज्ञान, नीति और जमीनी स्तर के अनुभवों के बीच सेतु का कार्य किया; इसने यह सुनिश्चित किया कि सूखा, शीत लहर, कीटों के हमले और ओलावृष्टि के प्रबंधन पर आने वाले राष्ट्रीय दिशा-निर्देश समावेशी, क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप और किसान-केंद्रित हों। इस कार्यशाला से प्राप्त सुझाव पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में कृषि आपदा जोखिम प्रबंधन के ढांचों को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

सूखा नियमावली संशोधन-2020 और ओलावृष्टि, शीत लहर/पाला तथा कीट प्रकोप पर दिशा-निर्देशों के निर्माण पर क्षेत्रीय (केंद्रीय) हितधारक परामर्श कार्यशाला,  
20 फरवरी 2026, उत्तर प्रदेश



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से, 20 फरवरी 2026 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्-केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, झांसी में एक क्षेत्रीय हितधारक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला सूखा मैनुअल-2020 के संशोधन तथा ओलावृष्टि, शीत लहर/पाला और कीट प्रकोप से संबंधित व्यापक राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के निर्माण हेतु चल रही परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य भारत के मध्य क्षेत्र के कृषि क्षेत्र को प्रभावित करने वाली चुनौतियों पर विचार करना था।

इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के वरिष्ठ अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ और प्रगतिशील किसान एक साथ शामिल हुए। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए, NIDM के परियोजना निदेशक श्री शिव नारायण सिद्ध ने क्षेत्रीय परामर्श की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की और राष्ट्रीय नीतिगत ढांचों में जमीनी वास्तविकताओं को शामिल करने के महत्व पर जोर दिया। अनुसंधान संस्थानों और तकनीकी एजेंसियों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने उभरती जलवायु परिवर्तनशीलता, चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और मध्य क्षेत्र में वर्षा-आधारित कृषि की बढ़ती संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला।

कार्यशाला में सूखा जोखिम आकलन, शीत लहर एवं पाला के प्रभाव, ओलावृष्टि से होने वाली फसल को नुकसान, तथा कीट प्रकोप प्रबंधन पर केंद्रित तकनीकी चर्चाएं आयोजित की गईं। विशेषज्ञों ने प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान प्रणाली को

मजबूत करने, मौसम संबंधी परामर्शों और कृषि विस्तार सेवाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, तथा रिमोट सेंसिंग और डिजिटल फसल निगरानी प्रणालियों जैसे वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही, कीट निगरानी तंत्र में सुधार करने और स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप क्षेत्र-विशेष के लिए फसल परामर्श विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया गया।

किसानों ने चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया, और वर्षा की अनिश्चितता, लंबे समय तक सूखे की स्थिति, तापमान में वृद्धि, स्थानीय ओलावृष्टि और बार-बार होने वाले कीट प्रकोपों के अपने प्रत्यक्ष अनुभव साझा किए। उन्होंने समयबद्ध और उपयोगी सलाह, फसल बीमा की सरल प्रक्रियाओं, पारदर्शी मुआवजे की व्यवस्था तथा स्थानीय भाषाओं में प्रारंभिक चेतावनी के प्रभावी प्रसार की आवश्यकता पर जोर दिया। चर्चाओं में नीति निर्माण और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के बीच के अंतर को पाटने के महत्व को उजागर किया।

कार्यशाला इस समझ के साथ संपन्न हुआ कि संशोधित दिशा-निर्देश व्यावहारिक, किसान-केंद्रित और क्षेत्रीय रूप से उपयुक्त होने चाहिए। मध्य क्षेत्रीय परामर्श से प्राप्त सुझाव राष्ट्रीय स्तर पर कृषि आपदा जोखिम प्रबंधन ढांचे को सुदृढ़ करने तथा देशभर में जलवायु-रोधी और टिकाऊ कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

# सूखा नियमावली संशोधन-2020 और ओलावृष्टि, शीत लहर/पाला तथा कीट प्रकोप पर दिशा-निर्देशों के निर्माण पर क्षेत्रीय (पश्चिमी) हितधारक परामर्श कार्यशाला, 26 फरवरी 2026, राजस्थान



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से, 26 फरवरी 2026 को भाकृअनुप- केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (ICAR-CAZRI), जोधपुर में एक क्षेत्रीय हितधारक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला सूखा नियमावली-2020 के संशोधन और ओलावृष्टि, शीत लहर/पाला तथा कीट हमले पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के निर्माण की चल रही परामर्श प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में आयोजित की गई थी, जिसमें देश के शुष्क और अर्ध-शुष्क पश्चिमी क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया।

इस परामर्श सत्र में राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के प्रतिनिधियों के साथ-साथ कृषि वैज्ञानिकों, मौसम विज्ञान विशेषज्ञों, आपदा प्रबंधन पेशेवरों और प्रगतिशील किसानों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। डॉ. वी. के. सिंह, निदेशक, भाकृअनुप-केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR-CRIDA); डॉ. वी. के. राव, वैज्ञानिक, केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान (CRIDA); श्री राधे श्याम शर्मा, भारतीय मौसम विभाग (IMD), जयपुर; श्री एस. पी. तंवर, निदेशक, भाकृअनुप- केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (ICAR-CAZRI); और डॉ. जी. आर. मटोरिया, अतिरिक्त कृषि निदेशक (विस्तार) की उपस्थिति ने चर्चाओं को महत्वपूर्ण तकनीकी गहराई प्रदान की।

कार्यशाला में पश्चिमी भारत में सूखे की घोषणा, शीत लहर/पाला के प्रभावों, ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान के आकलन और कीट प्रकोप के प्रबंधन से जुड़ी क्षेत्र-विशेष की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिभागियों ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा सूखा घोषणा मानदंडों को सरल बनाने और उनमें अधिक लचीलापन लाने की आवश्यकता है, ताकि शुष्क परिदृश्यों में मौजूद कृषि-पारिस्थितिक विविधता, तापमान में वृद्धि, लंबे समय तक चलने वाले सूखे के दौर और सूक्ष्म-क्षेत्रीकरण (micro-zonation) की आवश्यकताओं को सही ढंग से दर्शाया जा सके। घोषणाओं में देरी और नियमावली-आधारित उपज आकलन तथा बीमा-आधारित अनुमानों के बीच विसंगति को लेकर भी चिंताएं व्यक्त की गईं।

सिंचाई और शमन उपायों पर हुई चर्चाओं में सूक्ष्म-सिंचाई प्रणालियों के विस्तार, भूजल पुनर्भरण संरचनाओं को सुदृढ़ करने, खेत-तालाबों के डिजाइनों में सुधार

करने और शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त जल-कुशल फसल किस्मों को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। किसानों ने इस बात पर जोर दिया कि प्रभावी मुआवजा सुनिश्चित करने और संकट को कम करने के लिए फसल कटाई से पहले समय पर सूखा घोषणा किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओलावृष्टि और कीटों के हमलों के संबंध में, प्रतिभागियों ने प्रभाव-आधारित मूल्यांकन ढांचों, बेहतर रडार-आधारित निगरानी और किसानों द्वारा सीधे फसल नुकसान की रिपोर्टिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कीटों के प्रकोप को उभरते हुए जोखिमों के रूप में बताया गया, जिसमें कपास और बागवानी फसलों में गंभीर संक्रमण शामिल हैं, जिनके लिए व्यवस्थित निगरानी प्रणालियों और आपदा प्रबंधन योजनाओं में स्पष्ट रूप से शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

चना और बागवानी फसलों पर शीत लहर और पाले के प्रभावों पर भी चर्चा की गई, जिसमें मुआवजे के मानदंडों में तापमान-संबंधी नुकसान की व्यवस्थित पहचान पर जोर दिया गया। भारतीय मौसम विभाग और कृषि अनुसंधान संस्थानों के विशेषज्ञों ने कृषि-मौसम संबंधी सलाह, रिमोट सेंसिंग उपकरणों और वास्तविक समय की निगरानी प्रणालियों को एक एकीकृत जोखिम मूल्यांकन ढांचे में शामिल करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

परामर्श का समापन राहत-केंद्रित दृष्टिकोणों से हटकर सक्रिय शमन रणनीतियों की ओर बढ़ने, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने, संस्थानों के बीच डेटा-साझाकरण में सामंजस्य स्थापित करने, बीमा तंत्र में सुधार करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा समन्वित जन संपर्क के माध्यम से किसानों की जागरूकता बढ़ाने के लिए कड़े सुझावों के साथ हुआ। जोधपुर में हुई चर्चाओं ने भारत के पश्चिमी शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में कृषि की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय रूप से अनुकूल, वैज्ञानिक रूप से आधारित और किसान-केंद्रित दिशा-निर्देशों की आवश्यकता की पुनः पुष्टि की।

कार्यशाला का समापन मेज़बान संस्थान भाकृअनुप- केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर और सभी प्रतिभागी हितधारकों को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ, जो देश में कृषि आपदा जोखिम प्रबंधन ढांचों को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

## भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (IDRN), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (NDMIS) एवं नॉलेज वर्टिकल्स पर राष्ट्रीय कार्यशाला, 02 मार्च 2026, दिल्ली



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने 2 मार्च 2026 को अपने दिल्ली परिसर में भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (IDRN), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (NDMIS) एवं नॉलेज वर्टिकल्स पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। यह क्षमता निर्माण पहल दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अधिकारियों की भागीदारी के साथ आयोजित की गई।

उद्घाटन सत्र में श्री मधुप व्यास, भा.प्र.से., कार्यकारी निदेशक, NIDM; प्रो. आमिर अली खान, विभागाध्यक्ष, आरआई एवं जीएमआर प्रभाग, NIDM; कर्नल मनोरम यादव, एसएम, संयुक्त निदेशक, NIDM; तथा डॉ. गरिमा अग्रवाल, वरिष्ठ सलाहकार एवं पाठ्यक्रम समन्वयक, NIDM की गरिमामयी उपस्थिति रही।

IDRN पर एक तकनीकी सत्र श्री रणदीप राणा, वरिष्ठ सलाहकार, NIDM द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रमुख विशेषताओं, संचालन संबंधी पहलुओं के साथ

लाइव डेमोंस्ट्रेशन एवं प्रायोगिक अभ्यास शामिल थे। IDRN डेटा अपडेट पर एक सत्र में डेटा की सटीकता और समयबद्धता में सुधार पर जोर दिया गया, जिसे पैनलिस्टों और प्रतिभागियों के सुझावों से और समृद्ध किया गया।

नॉलेज वर्टिकल्स पर आयोजित सत्र ने सर्वोत्तम प्रथाओं और साक्ष्य-आधारित आपदा जोखिम शासन को बढ़ावा देने में ज्ञान-साझाकरण प्लेटफॉर्म की भूमिका पर प्रकाश डाला। NDMIS उद्घाटन सत्र को गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन-1 के निदेशक श्री आशीष वी. गवई द्वारा संबोधित किया गया, जिसके पश्चात् श्री आशुतोष अवस्थी, उप निदेशक, गृह मंत्रालय तथा श्री पवन अरोड़ा, सहायक निदेशक, एनआईसी द्वारा प्रस्तुति दी गई।

लाइव प्रदर्शन और व्यावहारिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इस कार्यशाला ने राज्य और जिला अधिकारियों की क्षमताओं को मजबूत किया, जिससे भारत का डिजिटल आपदा प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र और सुदृढ़ हुआ।

# अन्य संस्थागत क्रियाकलाप

## आपदा प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु मालदीव के प्रतिनिधिमंडल का NIDM दौरा



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) ने 7 जनवरी 2026 को अपने दिल्ली परिसर में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), मालदीव के एक प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करना था। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री हिसान हसन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, NDMA मालदीव द्वारा किया गया।

यह दौरा NIDM के संकाय और प्रतिनिधिमंडल के बीच एक संवादात्मक सत्र के साथ संपन्न हुआ, जिसमें प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा आपदा प्रतिरोधक क्षमता के लिए संस्थागत क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई।

## आपदा जागरूकता में सिनेमा की भूमिका

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने PVR INOX Limited के सहयोग से 7 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में फिल्म 'Greenland: Migration' की एक विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक, श्री मधुप व्यास (भा.प्र.से.) ने आपदा प्रबंधन समुदाय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भाग लिया।

स्क्रीनिंग के बाद NDMA और NDRF तथा सिविल डिफेंस जैसी संबद्ध एजेंसियों के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ एक पैनल चर्चा आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में आपदा जोखिम को कम करने के लिए जन जागरूकता बढ़ाने, व्यावहारिक तैयारियों को बढ़ावा देने और सामुदायिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में सिनेमा की क्षमता पर प्रकाश डाला गया।



## सुदृढ़ पुनर्निर्माण के तरीकों के अध्ययन हेतु NIDM के प्रतिनिधिमंडल का कच्छ दौरा



श्री मधुप व्यास (भा.प्र.से.), कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात के कच्छ जिले का दौरा किया। इस दौरे का मकसद सुदृढ़ पुनर्निर्माण के तरीकों और आपदा के बाद पुनर्वास में 'Build Back Better' (पहले से बेहतर पुनर्निर्माण) के दृष्टिकोण का अध्ययन करना था। इस दौरे के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने कच्छ के जिला कलेक्टर श्री आनंद पटेल से मुलाकात की और इंप्रॉस्ट्रक्चर को मजबूत बनाने तथा आपदा से उबरने की योजना बनाने की रणनीतियों पर चर्चा की। टीम ने 'स्मृतिवन भूकंप स्मारक और संग्रहालय' का भी दौरा किया, जो आपदा के प्रति जागरूकता और सीखने का एक केंद्र है।

इसके अलावा, प्रतिनिधिमंडल ने 'गांधी नु गाम' (लुडिया) में स्थानीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। यह एक आदर्श गाँव है, जो 2001 के भुज भूकंप के बाद भूकंप-रोधी आवास, समुदाय के नेतृत्व में रिकवरी और आजीविका के टिकाऊ उपायों का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करता है।

## राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण संग्रहालय के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एवं राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (NCSM) के बीच सहयोग पर सहमति



श्री मधुप व्यास (भा.प्र.से.), कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 19-21 फरवरी 2026 के दौरान कोलकाता स्थित राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (NCSM) का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य एनआईडीएम रोहिणी, नई दिल्ली में प्रस्तावित राष्ट्रीय आपदा जोखिम

न्यूनीकरण (DRR) संग्रहालय की योजना और विकास पर चर्चा करना था। चर्चाओं में वैश्विक मानकों के अनुरूप, वास्तुकला की दृष्टि से आकर्षक और वित्तीय रूप से टिकाऊ संग्रहालय के निर्माण पर जोर दिया गया। इसके लिए एनसीएसएम के साथ संरचित सहयोग के तहत विस्तृत आर्किटेक्ट ब्रीफ, संदर्भ की शर्तें (Terms of Reference) और एक पारदर्शी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया तैयार करने पर सहमति बनी।

मुख्य बिंदुओं में इमर्सिव (डूबने जैसा अनुभव देने वाली) और अनुभवात्मक गैलरी डिजाइन विकसित करना, कॉर्पस-आधारित वित्तीय मॉडल अपनाना, राजस्व तंत्र के माध्यम से दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना, तथा कैफे और इंटरैक्टिव स्पेस जैसी आगंतुक-केंद्रित सुविधाओं का समावेश शामिल था। एनसीएसएम संग्रहालय और साइंस सिटी के दौरे से आधुनिक प्रदर्शनी पद्धतियों और अनुभवात्मक शिक्षण के दृष्टिकोणों की जानकारी मिली।

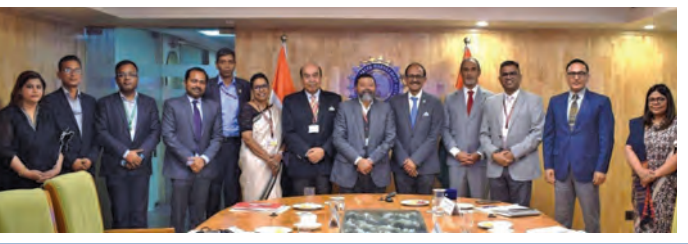
यह सहमति बनी कि एनआईडीएम योजना ढांचे की शुरुआत करेगा, जबकि एनसीएसएम निरंतर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यह पहल आपदा जागरूकता, शिक्षा और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एक विश्व-स्तरीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण संग्रहालय की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

## आपदा-रोधी सांस्कृतिक विरासत के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (IGNCA) के बीच सहयोग पर सहमति

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक श्री मधुप व्यास (भा.प्र.से.) ने 6 मार्च 2026 को सुश्री नाज़िया खान के साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (IGNCA) के सचिव श्री सच्चिदानंद जोशी के साथ नई दिल्ली में एक बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जागरूकता पहलों में सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को शामिल करने के लिए सहयोग की संभावनाओं को तलाशना था। इसमें प्रस्तावित NIDM आपदा प्रबंधन संग्रहालय के लिए सहयोग और जागरूकता गतिविधियों के लिए IGNCA के क्षेत्रीय केंद्रों के उपयोग जैसे विषय शामिल थे। चर्चा के मुख्य बिंदुओं में संग्रहालय की रूपरेखा तैयार करने में

IGNCA का सहयोग, जागरूकता कार्यक्रमों के लिए क्षेत्रीय केंद्रों का उपयोग, सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) सामग्री का प्रसार, तथा पारंपरिक ज्ञान और भारतीय ज्ञान प्रणालियों का दस्तावेजीकरण शामिल था। दोनों संस्थानों ने प्रभावी संचार के लिए सांस्कृतिक माध्यमों के उपयोग पर भी विचार-विमर्श किया। इस बात पर सहमति बनी कि संस्कृति-आधारित आपदा जागरूकता और सामुदायिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त पहलों, जागरूकता कार्यक्रमों और ज्ञान के आदान-प्रदान के माध्यम से आपसी सहयोग को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।

## राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) के साथ उच्च स्तरीय संवाद में भागीदारी



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) के अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि और संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय के प्रमुख श्री कमल किशोर की यात्रा के दौरान एक उच्च-स्तरीय चर्चा में भाग लिया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक श्री मधुप व्यास (भा.प्र.से.) ने सुश्री नाज़िया खान के साथ मिलकर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य और विभागाध्यक्ष (HoD) डॉ. कृष्ण एस. वत्स की अध्यक्षता में हुई चर्चाओं में भाग लिया।

इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी तालमेल को मजबूत करना, तथा 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडआई फ्रेमवर्क' के तहत निर्धारित प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना था; इसमें G20 और BRICS जैसे वैश्विक मंचों के माध्यम से किए जाने वाले सहयोग पर भी विशेष जोर दिया गया।



## राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एवं संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय के बीच रणनीतिक संवाद



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अधिकारियों ने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) के नेतृत्व के साथ एक उच्च-स्तरीय बातचीत में हिस्सा लिया। इस बातचीत का मकसद आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को मजबूत करना और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक श्री मधुप व्यास (भा.प्र.से.) ने प्रो. आमिर अली खान और सुश्री नाजिया खान के साथ मिलकर, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि श्री कमल किशोर और संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण के एशिया और प्रशांत क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख श्री मार्को टोस्कानो-रिवाल्टा के साथ चर्चा की।

इस चर्चा का मुख्य जोर रणनीतिक सहयोग को बढ़ाना, ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना और 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क' के अनुरूप संस्थागत क्षमता निर्माण को मजबूत करना था। चर्चा के मुख्य बिंदुओं

### आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भारतीय विश्वविद्यालय और संस्थान नेटवर्क (IUINDRR) - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहल: उच्च शिक्षा और अनुसंधान के मुख्यधारा में आपदा जोखिम न्यूनीकरण का समावेश



**उच्च शिक्षा में आपदा जोखिम न्यूनीकरण :** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) ने, 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भारतीय विश्वविद्यालय और संस्थान नेटवर्क' (IUINDRR) के माध्यम से, उच्च शिक्षा में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

इस पहल के बाद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहित किया है कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप, शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से स्नातक स्तर पर 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन' पर आधारित 2-क्रेडिट का 'कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम' शुरू करें।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने एक ऐसा मॉडल पाठ्यक्रम तैयार किया है

#### अनुसंधान सलाहकार समिति (RAC) की बैठक

अनुसंधान सलाहकार समिति (RAC) की बैठक 2 मार्च 2026 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा हेतु आयोजित की गई। तीन श्रेणियों के अंतर्गत कुल 331 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिनका RAC सदस्यों द्वारा गहन मूल्यांकन किया गया। इन सदस्यों में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के संकाय सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी और एक बाहरी विशेषज्ञ - इंदिरा गांधी दिल्ली



में बहु-स्तरीय शासन को आगे बढ़ाना, जोखिम-जागरूक विकास को बढ़ावा देना और समन्वित वैश्विक प्रयासों के माध्यम से उभरते तथा जटिल जोखिमों से निपटना शामिल था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया, और साथ ही एक अधिक सुदृढ़ और आपदा से निपटने के लिए तैयार विश्व के निर्माण के उद्देश्य से वैश्विक साझेदारियों, क्षमता विकास पहलों और ज्ञान नेटवर्कों में सक्रिय रूप से योगदान देने का भी संकल्प लिया।



जो आपदा की तैयारी और सामुदायिक प्रतिरोधक क्षमता से जुड़े सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक कौशल के साथ जोड़ता है; इसके साथ ही, जागरूकता और व्यवहारगत बदलाव को बढ़ावा देने के लिए कॉलेजों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्लब स्थापित करने हेतु दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

**अनुसंधान:** आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में अनुसंधान को सुदृढ़ करने के लिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने तीन प्रमुख पहलें शुरू की हैं, जो इस प्रकार हैं: डॉक्टरल फलोशिप कार्यक्रम; अनुसंधान परियोजनाएँ/अध्ययन: कार्य एवं नवाचार अनुसंधान; और सर्वश्रेष्ठ पीएचडी शोध-प्रबंध रैंकिंग।

तकनीकी विश्वविद्यालय (महिला) में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख प्रो. एस.आर.एन. रेड्डी शामिल थे। विस्तृत विचार-विमर्श और चर्चाओं के उपरांत, समिति ने तीनों श्रेणियों के अंतर्गत प्राप्त 331 आवेदनों में से अंतिम मूल्यांकन हेतु 36 प्रस्तावों को शॉर्टलिस्ट किया।

## शैक्षणिक अनुसंधान परिषद (ARC) की बैठक

शैक्षणिक अनुसंधान परिषद (ARC) की दूसरी बैठक 16 मार्च 2026 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली में श्री मधुप व्यास (भा.प्र.से., कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम) की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में NIDM, MHA, NDMA और देश के अग्रणी संस्थानों के विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिनमें कुमाऊं विश्वविद्यालय, IIM बोधगया, IIT गुवाहाटी, INCOIS, IMD, IIM लखनऊ और Geohazards International शामिल हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए

उम्मीदवारों द्वारा कुल 36 प्रस्तुतियाँ दी गईं। विशेषज्ञ सदस्यों ने इन प्रस्तुतियों के आधार पर अंतिम मूल्यांकन किया, जिसके बाद प्रत्येक उम्मीदवार के साथ प्रश्न-उत्तर सत्र आयोजित किया गया। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सहायता हेतु 5 अनुसंधान परियोजनाओं और 5 डॉक्टरल फेलो का चयन किया गया, तथा मान्यता प्रदान करने हेतु 2 सर्वश्रेष्ठ Ph.D. शोध-प्रबंधों को चुना गया।

## लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में एनआईडीएम का प्रतिनिधित्व



अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर, 'बदलते जलवायु में स्थानीय प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण' विषय पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 09-03-2026 से 13-03-2026 तक एलबीएसएनए, मसूरी में आयोजित किया गया, जिसमें देशभर की महिला वैज्ञानिकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस पहल ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका तथा जलवायु प्रतिरोधक क्षमता के प्रयासों में उनके बढ़ते नेतृत्व को रेखांकित किया।

इस कार्यक्रम में एनआईडीएम की तरफ से सुश्री विनीता कुमारी एवं डॉ. कुंदन



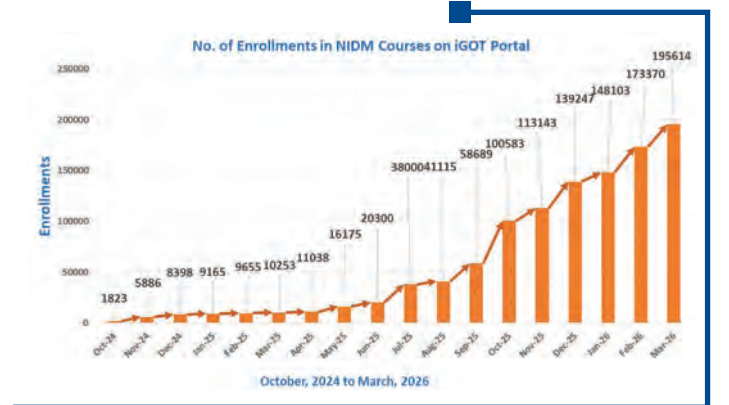
देवल ने भाग लिया, जिससे डीआरआर के क्षेत्र में महिला पेशेवरों को सशक्त बनाने के प्रति एनआईडीएम की प्रतिबद्धता प्रदर्शित हुई। इस कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्षण पीयर लर्निंग एक्सरसाइज़ और समूह गतिविधियाँ थीं, जिनमें सुश्री विनीता कुमारी ने व्यावहारिक और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप समाधान सुझाने के लिए प्रथम पुरस्कार और सर्टिफिकेट ऑफ़ मेरिट प्राप्त किया। यह सम्मान न केवल व्यक्तिगत उत्कृष्टता को रेखांकित करता है, बल्कि आपदा-रोधी क्षमता के क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता और बदलाव लाने वालों के रूप में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाता है।

## एनआईडीएम डिजिटल लर्निंग पहल

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM), माननीय प्रधानमंत्री के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए 10-सूत्रीय एजेंडा के बिंदु 6 को विशेष रूप से रेखांकित करते हुए, जो आपदा जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्षमता निर्माण में नए कीर्तिमान स्थापित करना जारी रखे हुए है। iGOT कर्मयोगी जैसे प्लेटफॉर्म और अपने समर्पित ई-लर्निंग पोर्टल का उपयोग करते हुए, NIDM शासन व्यवस्था में आपदा प्रतिरोधक क्षमता (Disaster Resilience) को सहज रूप से एकीकृत कर रहा है, तथा दक्षता-आधारित, व्यावहारिक और नीतिगत रूप से प्रासंगिक शिक्षण समाधान प्रदान कर रहा है।

iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत, NIDM नौ विविध पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है, जो अंग्रेज़ी, हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मलयालम और ओड़िया जैसी भाषाओं में उपलब्ध हैं। ये पाठ्यक्रम समावेशी होने के साथ-साथ देशव्यापी भी हैं। इस पहल के बढ़ते प्रभाव को इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि अब तक 1,95,614+ लोगों ने नामांकन लिया जिसमें से 1,17,692+ लोगों द्वारा उपलब्ध पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है और औसत 4.5/5 को प्रभावशाली शिक्षार्थी रेटिंग प्राप्त हुई है, जो सामग्री की प्रासंगिकता और उत्कृष्टता को रेखांकित करती है।

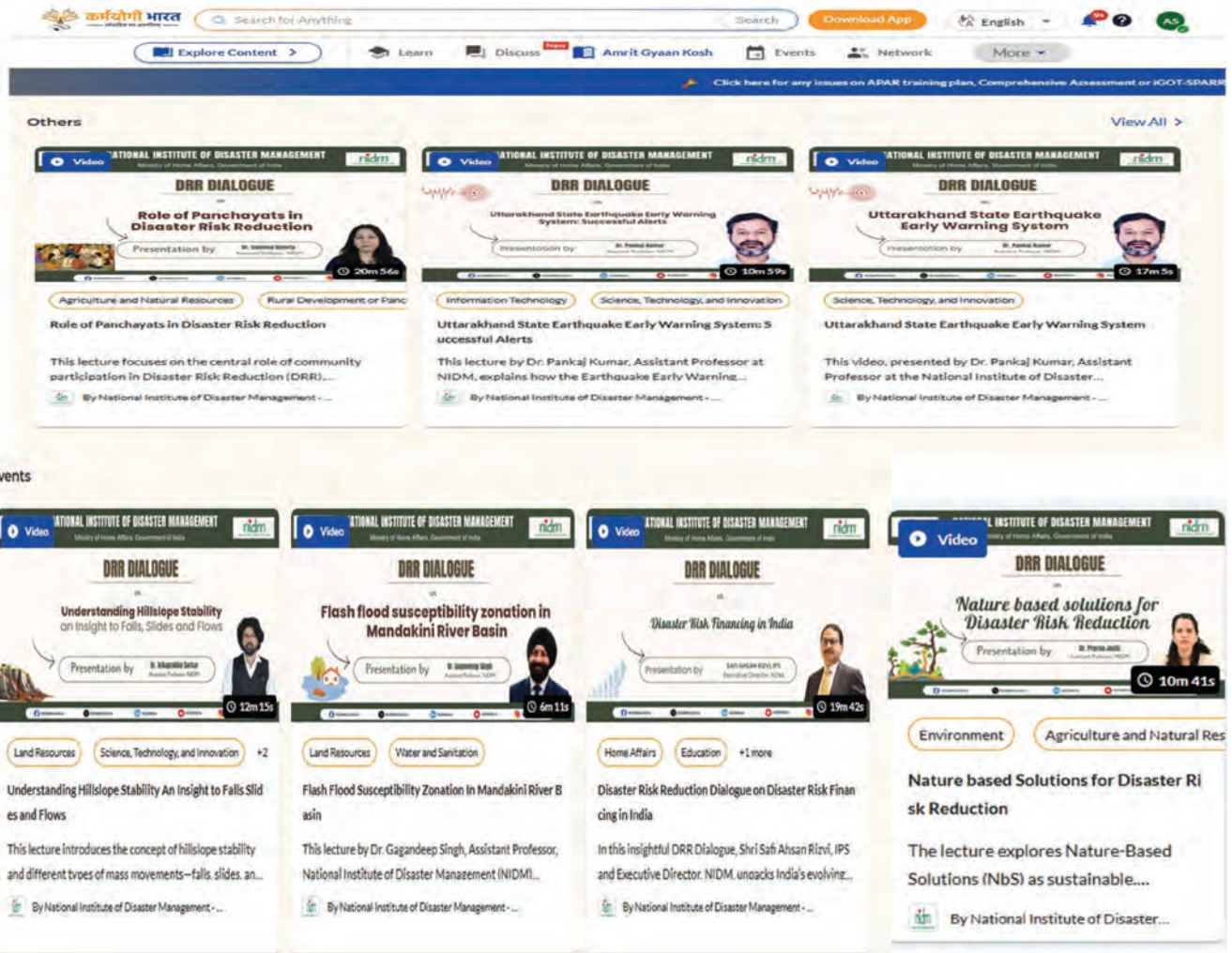
इसके अतिरिक्त, NIDM के ई-लर्निंग कार्यक्रमों में एक प्रमुख (Basic) और नौ विषयगत (Thematic) पाठ्यक्रम शामिल हैं। अपनी पहल को और सशक्त करते हुए, NIDM वार्षिक क्षमता निर्माण योजना (ACBP) के अंतर्गत अपने पाठ्यक्रमों का विस्तार कर रहा है।



NIDM में आयोजित DRR संवाद व्याख्यान श्रृंखला (DRR Dialogue Lecture Series) आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उभरते विषयों पर ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए एक सशक्त मंच के रूप में कार्य करती है, जो विशेषज्ञों, प्रैक्टिशनर्स और नीति-निर्माताओं को एक साथ लाती है। यह श्रृंखला अनुसंधान, नीतिगत संवाद और व्यावहारिक अनुभव को एकीकृत करने के उद्देश्य से तैयार की गई है, जिसमें अत्याधुनिक विषयों पर चर्चाएँ होती हैं, और इनके रिकॉर्ड किए गए सत्रों को दीर्घकालिक क्षमता निर्माण हेतु डिजिटल शिक्षण संसाधनों के रूप में संकलित किया जाता है।

अमृत ज्ञान कोश के अंतर्गत NIDM की DRR संवाद श्रृंखला ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य करती है, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उभरते पहलुओं पर संवाद को आगे बढ़ाती है। इस श्रृंखला में आपदा जोखिम वित्तपोषण, प्रकृति-आधारित समाधान, मंदाकिनी बेसिन में फ्लैश फ्लड की संवेदनशीलता, और उत्तराखंड में भूकंप प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है।

इसी क्रम में, हालिया सत्रों में पंचायती राज की भूमिका, मनोसामाजिक सहयोग, घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (IRS), IUCN के प्रकृति-आधारित समाधान मानक, तथा ढलान स्थिरता (Hillslope Stability) जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे NIDM की राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधक क्षमता के ज्ञान केंद्र के रूप में भूमिका और सुदृढ़ हुई है।



## पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण

### ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के एकीकरण पर ऑनलाइन वेबिनार

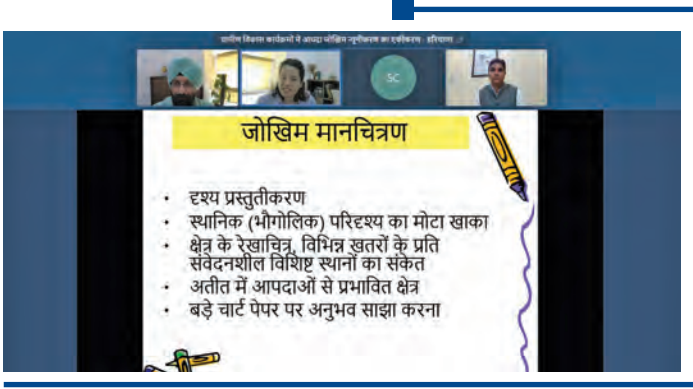
NIDM द्वारा iGOT प्लेटफॉर्म और NIDM ई-लर्निंग पोर्टल के माध्यम से पेश किए जाने वाले नियमित पाठ्यक्रमों के अलावा, यह संस्थान विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और वेबिनार श्रृंखलाएँ भी आयोजित करता है, जिनका मुख्य उद्देश्य ज़मीनी स्तर पर व्यापक पहुँच सुनिश्चित की जा सके। पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और स्थानीय शासन प्रणालियों की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए एक विशेष ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे कि वे ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) को एकीकृत कर सकें।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच आपदा जोखिमों तथा ग्रामीण-स्तरीय विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण

को शामिल करने के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इसमें आपदा-रोधी समुदायों के निर्माण और ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्यधारा में लाने में स्थानीय शासन संस्थाओं की भूमिका पर जोर दिया गया।

तकनीकी सत्रों में आपदा प्रबंधन ढाँचे, पंचायतों की भूमिका, ग्राम आपदा प्रबंधन योजनाओं का GPDP के साथ तालमेल, जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन तथा प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों जैसे प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया; जिससे ज़मीनी स्तर पर जोखिम-आधारित योजना बनाने की क्षमताओं को मजबूती मिली।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल विषयों का विवरण निम्नलिखित है-



राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	जिलों की संख्या	ग्राम पंचायतें एवं समकक्ष इकाइयां	एनआईडीएम द्वारा समाविष्ट पंचायत/गाँव	कुल प्रतिभागियों की संख्या
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	02	70	49	63
आंध्र प्रदेश	16	13325	26	60
अरुणाचल प्रदेश	27	2108	45	56
असम	33	2664	54	58
बिहार	38	8053	1038	1154
छत्तीसगढ़	33	11693	2213	2956
चंडीगढ़	01	उपलब्ध नहीं		
दिल्ली	11	उपलब्ध नहीं		
गोवा	02	191	44	53
गुजरात	33	14621	51	51
हरियाणा	22	6230	1749	1940
हिमाचल प्रदेश	12	3615	731	899
जम्मू और कश्मीर	20	4291	1002	1096
झारखंड	24	4347	3217	3575
कर्नाटक	31	5949	371	373
केरल	14	941	42	42
लद्दाख	07	193	123	137
लक्षद्वीप	01	10	10	22
मध्य प्रदेश	55	23011	1249	1695
महाराष्ट्र	36	27969	444	528
मणिपुर	16	3810	150	159
मेघालय	12	6982	142	159
मिजोरम	11	855	165	235
नागालैंड	17	1327	451	541
ओडिशा	30	6794	1311	1516
पुडुचेरी	04	108	140	258
पंजाब	23	13236	4736	9137
राजस्थान	50	13130	2500	3535
सिक्किम	06	199	44	52
तमिलनाडु	38	12482	497	622
तेलंगाना	33	12815	362	375
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	03	50	98	340
त्रिपुरा	08	1194	470	670
उत्तराखंड	13	7817	179	214
उत्तर प्रदेश	75	57695	7161	9507
पश्चिम बंगाल	23	3339	101	115
<b>कुल</b>	<b>780</b>	<b>271114</b>	<b>30965</b>	<b>42193</b>

\*पंचायतों का विवरण पंचायती राज मंत्रालय की वेबसाइट से 29 दिसंबर 2025 को प्राप्त किया गया।

बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप और सूखा जैसी आपदाएँ विश्वभर में मानव जीवन, अवसंरचना तथा आर्थिक स्थिरता के लिए निरंतर खतरा बनी हुई हैं। जलवायु परिवर्तन, तीव्र शहरीकरण और पर्यावरणीय क्षरण ने इन आपदाओं के जोखिम और श्रृंखलाबद्ध प्रभावों को और अधिक बढ़ा दिया है। इस संदर्भ में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) को सुदृढ़ करने के लिए एक सशक्त उपकरण के रूप में उभरा है, जो पूर्वानुमान, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, तैयारी, प्रतिक्रिया तथा पुनर्वास में सुधार लाती है।

उपग्रहों, सेंसरों और ऐतिहासिक अभिलेखों से प्राप्त विशाल डेटा का विश्लेषण करके AI जटिल आंकड़ों को उपयोगी जानकारी में परिवर्तित करता है, जिससे संबंधित प्राधिकरण संभावित खतरों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और आपदाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं।

DRR में AI का एक प्रमुख अनुप्रयोग प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण है। AI और मशीन लर्निंग (ML) एल्गोरिथ्म मौसम एवं पर्यावरण संबंधी बड़े पैमाने के डेटा का विश्लेषण कर पैटर्न की पहचान करते हैं और अधिक तेज एवं सटीक पूर्वानुमान प्रदान करते हैं। उदाहरणस्वरूप, AI मॉडल वर्षा, मिट्टी की नमी तथा ढाल स्थिरता के मापदंडों को मिलाकर पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसी प्रकार, AI नदी प्रवाह और वर्षा पैटर्न का विश्लेषण कर बाढ़ जोखिम का आकलन तथा प्रभावित क्षेत्रों का अनुमान लगा सकता है। चक्रवात और बाढ़ पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए भी AI आधारित उपकरणों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है।

AI 'डिजिटल ट्विन' के विकास को भी संभव बना रहा है, जो शहरों, अवसंरचना और भवनों की आभासी प्रतिकृतियाँ होती हैं। ये प्रणालियाँ सेंसरों और भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म से प्राप्त वास्तविक समय डेटा को एकीकृत कर आपदा परिदृश्यों का अनुकरण करती हैं और संभावित प्रभावों का आकलन करती हैं। शहरी आग या भवन ढहने जैसी आपदा स्थितियों में डिजिटल ट्विन भवन संरचना, निकासी मार्ग और फंसे हुए लोगों की संभावित उपस्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर बचाव कार्यों को अधिक प्रभावी बनाते हैं।

AI का एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान डेटा एकीकरण और निर्णय में है। आपदा प्रबंधन में अक्सर विभिन्न एजेंसियों के बीच डेटा बिखरा हुआ होता है। AI उपग्रह चित्रों, सोशल मीडिया और मौसम संबंधी डेटाबेस जैसे स्रोतों से संरचित एवं असंरचित डेटा को एकीकृत कर प्राधिकरणों को क्षति का आकलन करने, प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने और तैयारी तथा राहत कार्यों को प्राथमिकता देने में सक्षम बनाता है।

AI आपदा प्रतिक्रिया कार्यों को भी परिवर्तित कर रहा है। उपग्रह-आधारित AI विश्लेषण आपदा के बाद ध्वस्त इमारतों, जलमग्न क्षेत्रों और अवरुद्ध सड़कों की पहचान कर सकता है। AI संचालित ड्रोन और रोबोट खतरनाक या दुर्गम क्षेत्रों में खोज एवं बचाव अभियानों में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, AI आधारित संचार प्रणालियाँ समुदायों तक प्रारंभिक चेतावनी और महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचाकर अंतिम छोर तक सूचना प्रसार को बेहतर बनाती हैं।

हालांकि इसकी अपार संभावनाओं के बावजूद, कुछ चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, जैसे सीमित कम्प्यूटेशनल अवसंरचना, डेटा साझाकरण में बाधाएँ और नैतिक चिंताएँ। AI प्रणालियों को मानव निर्णय-निर्माण का विकल्प नहीं, बल्कि सहयोगी बनना चाहिए, जिससे मानव-केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित हो सके।

उपयुक्त अवसंरचना और शासन ढाँचे के साथ 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत सेमीकंडक्टर निर्माण जैसी योजनाएँ, जैसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इंडिया AI मिशन, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs) के उत्पादन को बढ़ावा देंगी। इससे स्वदेशी AI मॉडल, मशीन लर्निंग एल्गोरिथ्म, बड़े भाषा मॉडल (LLMs) तथा रोबोटिक्स के विकास को गति मिलेगी।

हाल ही में, इंडिया AI समिट 2026 के दौरान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने 20 फरवरी 2026 को 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण में तकनीक के उपयोग की कमी को दूर करने हेतु AI आधारित प्रतिरोधक क्षमता' विषय पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। अतः आपदा जोखिम न्यूनीकरण का भविष्य पारंपरिक वैज्ञानिक ज्ञान और संस्थागत ढाँचों के साथ AI के प्रभावी एकीकरण में निहित है। इस प्रकार, AI आपदा प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करने तथा एक सुरक्षित और अधिक सक्षम भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

# प्रकृति-आधारित समाधान एवं पारिस्थितिकी-आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण : राज्यों द्वारा अनुकूलन के उपाय

डॉ. कुंदन देवल  
परामर्शदाता, एनआईडीएम

परिवर्तनशील जलवायु और इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक मौसमीय घटनाओं के कारण बाढ़, सूखा, चक्रवात और अन्य जल संबंधी आपदाओं की घटनाएँ लगातार और श्रृंखलाबद्ध रूप से बढ़ रही हैं। विशेष रूप से भारत में, ये जोखिम जीवनयापन, अवसंरचना और पारिस्थितिक तंत्र के लिए गंभीर खतरे पैदा करते हैं। अब यह धीरे-धीरे मान्यता प्राप्त हो रही है कि पारंपरिक आपदा प्रबंधन दृष्टिकोणों के साथ-साथ पारिस्थितिकी आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Eco-DRR) और प्रकृति-आधारित समाधान (Nature-based Solutions, NbS) जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से मुकाबला करने और स्थानीय अनुकूलन के प्रभावी तरीकों के रूप में उभरे हैं, जो आपदा जोखिम को कम करते हुए जैव विविधता संरक्षण और जलवायु सहनशीलता को बढ़ावा देते हैं।

पारिस्थितिकी आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण का अर्थ है पारिस्थितिक तंत्र का निरंतर प्रबंधन, संरक्षण और पुनर्स्थापना, जिससे कि आपदा जोखिम कम हो और समुदायों तथा जीवनयापन के लिए प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो। ये उपाय प्राकृतिक पारिस्थितिक कार्यों जैसे कि बाढ़ नियमन, तटीय संरक्षण, और मृदा स्थिरीकरण को बनाए रखकर जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण दोनों में योगदान करते हैं। वैश्विक ढांचे जैसे जैव विविधता सम्मेलन (CBD), आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क, और पेरिस समझौता पारिस्थितिकी आधारित दृष्टिकोणों को जलवायु और आपदा नीतियों में शामिल करने के महत्व को लगातार बढ़ा रहे हैं।

भारत के विविध पारिस्थितिकी तंत्र, जिनमें जंगल, मैंग्रोव, आर्द्र भूमि और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं, आपदा जोखिम कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और समुदायों को जलवायु संबंधित खतरों से बचाने वाले प्राकृतिक अवसंरचना का काम करते हैं। प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं:

- **वन पारिस्थितिकी तंत्र** : ढलानों को स्थिर करने और मिट्टी के कटाव को कम करने में मदद करता है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरों में कमी आती है। जलाधार पुनर्स्थापना और वनस्पति आवरण पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने और जल प्रवाह को नियमित करने में भी मदद करते हैं।
- **तटीय पारिस्थितिकी तंत्र** : चक्रवात और तूफानी लहरों से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैंग्रोव वन जैविक अवरोधों के रूप में कार्य करते हैं, लहरों की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और तटीय कटाव को कम करते हैं।
- **आर्द्रभूमि** : भारी वर्षा की घटनाओं के दौरान अतिरिक्त पानी संग्रहीत करके बाढ़ को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी तरह, घास के मैदान और शुष्क भूमि के पारिस्थितिकी तंत्र सूखा से बचाव की क्षमता को बढ़ाते हैं, मिट्टी की नमी बनाए रखते हैं और पशुपालन पर आधारित आजीविका को सहारा देकर, सूखे का सामना करने की क्षमता को मजबूत बनाते हैं।



चित्र 1 : जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और मानव कल्याण के समाधान हेतु प्रकृति आधारित उपाय

भारत में, जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाएँ (SAPCCs) उप-राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु अनुकूलन और शमन रणनीतियों को लागू करने के लिए प्राथमिक नीतिगत साधनों के रूप में कार्य करती हैं। कई राज्यों ने जलवायु समुत्थानशीलता और आपदा जोखिम को कम करने के लिए प्रमुख रणनीतियों के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित दृष्टिकोणों, जैसे-वन संरक्षण, जलाधार प्रबंधन, मैंग्रोव पुनर्स्थापना और आर्द्रभूमि संरक्षण को शामिल किया है।

**तालिका 01: प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण दृष्टिकोणों का विवरण**

क्रमांक	पारिस्थितिकी तंत्र	प्राकृतिक उपाय	निवारित आपदा	उदाहरण क्षेत्र/राज्य
1	वन पारिस्थितिकी	वनीकरण और सतत वन प्रबंधन	भूस्खलन, मिट्टी कटाव, बाढ़	उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश
2	मैंग्रोव पारिस्थितिकी	मैंग्रोव पुनर्स्थापना और संरक्षण	चक्रवात और तूफानी लहरें	ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात
3	आर्द्रभूमि और बाढ़ का मैदान	आर्द्रभूमि संरक्षण और बाढ़ के मैदान का प्रबंधन	बाढ़ नियंत्रण	असम, बिहार, उत्तर प्रदेश
4	जलाधार पारिस्थितिकी	जलाधार विकास और मृदा संरक्षण	सूखा और जल संकट	राजस्थान, महाराष्ट्र
5	तटीय पारिस्थितिकी	तटीय सुरक्षा बेल्ट और पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापना	तटीय कटाव और चक्रवात	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश

भारत के SAPCCs पारिस्थितिकी आधारित दृष्टिकोणों को जलवायु अनुकूलन रणनीतियों के रूप में अपनाने की बढ़ती मान्यता को दर्शाते हैं। कई राज्यों ने अपने जलवायु कार्य योजनाओं में पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापना और जैव विविधता संरक्षण उपायों को शामिल किया है। उदाहरण के लिए, हिमालयी राज्य भूस्खलन और हिमनदीय खतरों से निपटने के लिए वन संरक्षण और जलाधार प्रबंधन को प्राथमिकता देते हैं। तटीय राज्य जैसे ओडिशा, तमिलनाडु, और पश्चिम बंगाल चक्रवात जोखिम कम करने के लिए मैंग्रोव पुनर्स्थापना और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अर्ध-शुष्क राज्य सूखा और जल-संकट को दूर करने के लिए जलाधार विकास और निरंतर भूमि प्रबंधन पर जोर देते हैं।

ये पारिस्थितिकी आधारित हस्तक्षेप अक्सर वन, कृषि, जल संसाधन और ग्रामीण विकास क्षेत्रों को शामिल करने वाले एकीकृत कार्यक्रमों के माध्यम से लागू किए जाते हैं। कई मामलों में, राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे जलाधार विकास और ग्रामीण रोजगार योजनाएँ भी पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापना और आपदा के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में योगदान करती हैं।

जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाओं में पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित उपायों को शामिल करना, जलवायु समुत्थानशीलता बनाने में पारिस्थितिकी की भूमिका को लेकर बढ़ती नीतिगत पहचान को दर्शाता है।

राज्यों में पारिस्थितिकी-आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण का विस्तार करने के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली कार्यक्रमों को मजबूत बनाना, निगरानी ढाँचों में सुधार करना और विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। जैसे-जैसे भारत, 'जैव विविधता पर कन्वेंशन' (CBD) सहित विभिन्न वैश्विक पर्यावरणीय समझौतों के लिए अपनी राष्ट्रीय रिपोर्ट तैयार कर रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित उपायों का दस्तावेजीकरण इस बात की महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि जलवायु-रोधी विकास हासिल करने के लिए जैव विविधता संरक्षण और आपदा जोखिम न्यूनीकरण को किस प्रकार एकीकृत किया जा सकता है।

## आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के लिए डिजिटल ट्विन्स: वर्चुअल सिमुलेशन के माध्यम से तैयारी में परिवर्तन

डॉ. विशाल काटेकर  
रिसर्च एसोसिएट, एनआईडीएम

भारत दुनिया के सबसे अधिक आपदा-प्रवण देशों में से एक है, जहाँ लगभग 58% भूमि भूकंप के प्रति संवेदनशील है और 12% क्षेत्र बाढ़-प्रभावित है। इसके अलावा चक्रवात, सूखा, भूस्खलन और हीटवेव जैसे खतरों का भी जोखिम बना रहता है। तीव्र शहरीकरण, पर्यावरणीय क्षरण और बढ़ती जनसंख्या ने जोखिम और संवेदनशीलता को काफी बढ़ा दिया है, जिससे मध्यम स्तर की आपदाएँ भी अत्यधिक नुकसानदायक हो जाती हैं। यद्यपि भारत ने संस्थागत तंत्र और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ विकसित की हैं, फिर भी उन्नत रियल-टाइम भविष्यवाणी तकनीकों का उपयोग अभी सीमित है। इस संदर्भ में, डिजिटल ट्विन तकनीक आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मजबूत करने की बड़ी संभावना प्रदान करती है, जिससे प्रतिक्रियात्मक (reactive) दृष्टिकोण से हटकर पूर्वानुमान आधारित, सक्रिय और प्रतिरोधक क्षमता-आधारित शासन की ओर बढ़ा जा सकता है।

### आपदा जोखिम न्यूनीकरण में डिजिटल ट्विन्स

डिजिटल ट्विन एक गतिशील, रियल-टाइम वर्चुअल प्रतिरूप होता है, जो किसी भौतिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें भू-स्थानिक डेटा, ऐतिहासिक रिकॉर्ड, सेंसर इनपुट और उत्पादन विश्लेषण का समावेश होता है। इसका विकास मूल रूप से नासा द्वारा एयरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए किया गया था, लेकिन अब इसका उपयोग स्मार्ट सिटी, आधारभूत ढांचा प्रबंधन और जलवायु मॉडलिंग में व्यापक रूप से हो रहा है। स्थायी GIS प्लेटफॉर्म के विपरीत, डिजिटल ट्विन्स रियल-टाइम डेटा के साथ निरंतर अपडेट होते रहते हैं और विभिन्न आपदा परिदृश्यों का अनुकरण कर सकते हैं। ये नीति-निर्माताओं को निर्णयों का परीक्षण करने, लागत-लाभ का आकलन करने और आभासी वातावरण में प्रयोग करने की सुविधा देते हैं। इस प्रकार, डिजिटल ट्विन्स उन्नत निर्णय-सहायक प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं और सूक्ष्म, शहरी तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी आपदा जोखिम न्यूनीकरण को सक्षम बनाते हैं।

तालिका 1: पारंपरिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण से परे डिजिटल ट्विन्स के क्षेत्रवार अनुप्रयोग

क्षेत्र	सिमुलेशन का मुख्य केंद्र	जोखिम/समस्या का समाधान	नीतिगत परिणाम	उदाहरण स्वरूप क्षेत्र/राज्य
हिमनदीय प्रणाली (GLOFs)	हिमनद विस्तार, झील टूटने का मॉडलिंग, डाउनस्ट्रीम बाढ़ मार्ग	हिमालयी क्षेत्र में अचानक हिमनदीय झील के फटने से उत्पन्न बाढ़	प्रारंभिक चेतावनी योजना, अवसंरचना सुरक्षा, निकासी मानचित्रण	उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश
अवसंरचना प्रतिरोधक क्षमता	पुलों, सड़कों, मेट्रो प्रणालियों का संरचनात्मक तनाव मॉडलिंग	भूकंप, बाढ़, चक्रवात के दौरान ढहने का जोखिम	रेट्रोफिटिंग प्राथमिकता, निवेश अनुकूलन	ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात
शहरी पर्यावरण निगरानी	प्रदूषण फैलाव मॉडलिंग, हरित क्षेत्र मानचित्रण	वायु प्रदूषण हॉटस्पॉट, शहरी हीट आइलैंड	लक्षित शमन उपाय, हरित योजना नीतियाँ	असम, बिहार, उत्तर प्रदेश
जल संसाधन अनुकूलन	जलग्रहण क्षेत्र सिमुलेशन, भूजल पुनर्भरण, अंतर-घाटी विश्लेषण	जल की कमी और असमान वितरण	कुशल आवंटन, भंडारण योजना, फसल समायोजन	राजस्थान, महाराष्ट्र
भीड़ एवं सार्वजनिक सुरक्षा	भीड़ घनत्व सिमुलेशन, निकासी मार्ग अनुकूलन	भीड़भाड़ में भगदड़, अवरोध	रियल-टाइम प्रबंधन, संसाधन तैनाती	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश
कृषि	फसल उत्पादन मॉडलिंग, सिंचाई अनुसूची, मिट्टी की नमी विश्लेषण	जलवायु परिवर्तनशीलता और उत्पादन अनिश्चितता	जलवायु-परिवर्तन प्रतिरोधक क्षमता, कृषि, किसानों के जोखिम में कमी	उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश

सूक्ष्म स्तर पर, भवनों और महत्वपूर्ण सुविधाओं (जैसे अस्पताल और स्कूल) के डिजिटल ट्विन्स भूकंप के प्रभावों का मॉडल तैयार कर सकते हैं। वे संरचनात्मक प्रतिक्रिया, तनाव बिंदुओं का विश्लेषण करते हैं और रेट्रोफिटिंग उपायों, जैसे- बेस आइसोलेशन या शीयर वॉल्स की प्रभावशीलता का आकलन कर सकते हैं। वे लोगों के रहने के पैटर्न के आधार पर हताहत होने के जोखिम का अनुमान भी लगा सकते हैं, जिससे अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में भूकंप-रोधी सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता देने में मदद मिलती है। भूकंपों के अलावा, ये बाढ़, आग, लू, चक्रवात और भूस्खलन जैसी आपदाओं का भी सिमुलेशन करते हैं, जिससे नीति-निर्माताओं को कार्यान्वयन से पहले ही बेहतर जल निकासी, संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण और ऊँचाई में बदलाव जैसे शमन उपायों का परीक्षण करने की सुविधा मिलती है। शहर-स्तरीय डिजिटल ट्विन्स अवसंरचना और जनसंख्या डेटा को एकीकृत करके आपदा परिदृश्यों का अनुकरण करते हैं। उदाहरण के लिए, भूकंप मॉडलिंग मिट्टी के एम्प्लीफिकेशन प्रभावों का आकलन कर सकती है, इमारतों के ढहने की भविष्यवाणी कर सकती है, अवरुद्ध सड़कों की पहचान कर सकती है, निकासी मार्गों को अनुकूलित कर सकती है, और अस्पतालों की क्षमता का मूल्यांकन कर सकती है; जिससे तैयारी और प्रतिक्रिया योजना में सुधार होता है। वैश्विक स्तर पर, सिंगापुर के 'वर्चुअल सिंगापुर' और यूरोपीय संघ के 'डेस्टिनेशन अर्थ' जैसी पहलें शहरी नियोजन और जलवायु परिवर्तन की प्रतिरोधक क्षमता में डिजिटल ट्विन्स के महत्व को दर्शाती हैं। सूक्ष्म स्तर पर, राष्ट्रीय डिजिटल ट्विन्स भू-स्थानिक, सामाजिक-आर्थिक और जलवायु डेटा को एकीकृत करके जोखिम आकलन, संसाधन आवंटन, बीमा तंत्र और रियल-टाइम निगरानी को मजबूती प्रदान करते हैं। भारत में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और सर्वे ऑफ इंडिया जैसी एजेंसियाँ प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए ऐसे प्रणाली को सक्षम बना सकती हैं।

## भारतीय संदर्भ में चुनौतियाँ

डिजिटल ट्विन्स की बदलाव लाने की क्षमता के बावजूद, भारतीय संदर्भ में कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। एक बड़ी समस्या भू-स्थानिक डेटाबेस का बिखराव है, जिससे एकसमान और भरोसेमंद डेटा की उपलब्धता सीमित हो जाती है। विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच एकीकरण और तालमेल भी सीमित है, जिससे डेटा साझा करने और निर्णय लेने में कठिनाई पैदा होती है। इसके अलावा, अनुसंधान और विकास पर कम खर्च इस क्षेत्र में नवाचार को सीमित करता है। भारत अभी भी आयातित इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों पर निर्भर है, जिससे तकनीकी आत्मनिर्भरता को लेकर चिंताएँ पैदा होती हैं। एक और बड़ी कमी डिजिटल ट्विन्स के लिए एक एकीकृत नीतिगत ढाँचे का अभाव है, साथ ही डेटा प्रशासन, साइबर सुरक्षा और निजता से जुड़ी चिंताएँ भी बढ़ रही हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत संस्थागत तालमेल और व्यापक नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है।

## आगे की राह: एक स्वदेशी डिजिटल ट्विन मिशन की ओर

डिजिटल ट्विन्स की पूरी क्षमता का लाभ उठाने के लिए, भारत को एक रणनीतिक और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) के तहत एक 'राष्ट्रीय डिजिटल ट्विन मिशन' की स्थापना संस्थागत नेतृत्व और दिशा प्रदान कर सकती है। सेंसर-आधारित प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर रहने के बजाय, भारत बेहतर विस्तार क्षमता के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली उपग्रह इमेजरी का लाभ उठा सकता है। विदेशी तकनीकों पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी AI और सिमुलेशन उपकरण विकसित करने की भी आवश्यकता है। डिजिटल ट्विन्स को 'स्मार्ट सिटीज़' जैसी मौजूदा पहलों के साथ एकीकृत करने से शहरी प्रतिरोधक क्षमता और बढ़ सकता है। इसके अलावा, आपदा राहत कर्मियों को प्रशिक्षित करने और तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए सिमुलेशन-आधारित प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा सकता है। कुल मिलाकर, एक एकीकृत ढाँचा जो भूस्थानिक बुद्धिमता, पूर्वानुमान आधारित विश्लेषण और नीति सिमुलेशन को जोड़ता है, भारत में पूर्वानुमान-आधारित शासन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण को काफी मजबूत कर सकता है।

# आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के लिए 'कम्युनिटी ऑफ़ प्रैक्टिस' प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपदा जोखिम शासन का सुदृढीकरण

सुश्री विनीता कुमारी  
रिसर्च एसोसिएट, एनआईडीएम

तेजी से बढ़ती और जटिल होती आपदाओं के इस दौर में, आपदा जोखिम न्यूनीकरण की प्रभावशीलता केवल बुनियादी ढांचे और प्रतिक्रिया तंत्र पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि ज्ञान को कैसे साझा, रूपांतरित और संस्थागत किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में, 'कम्युनिटी ऑफ़ प्रैक्टिस' प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह प्रैक्टिशनरों, नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं, नवप्रवर्तकों, युवा उद्यमियों तथा आपदा विशेषज्ञों को एक साथ लाता है।

पारंपरिक सूचना प्रसार मॉडलों के विपरीत, जो प्रायः रैखिक और पदानुक्रमित होते हैं, एक CoP पीयर-टू-पीयर (आपसी) संवाद, वास्तविक समय में संवाद, सामूहिक समस्या समाधान और अंतर्निहित (tacit) ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन, तीव्र शहरीकरण, कमजोर बुनियादी ढांचा तथा सामाजिक-आर्थिक संवेदनशीलताओं जैसे कारकों के कारण कई तरह के खतरों में तेजी से तीव्र वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे परिदृश्य में, अकेले या अलग-अलग विभागों या संस्थानों के भीतर काम करना अक्सर प्रभावी नहीं होता, क्योंकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए कई-हितधारकों के बीच समन्वय और ज्ञान साझा करने की आवश्यकता होती है। इस कमी को CoP प्लेटफॉर्म दूर करता है, क्योंकि यह विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में काम करने वाले अलग-अलग संस्थानों, क्षेत्रों और संगठनों को एक साथ जोड़ता है।

CoP वैश्विक स्तर से लेकर जिलों और समुदायों तक ज्ञान, अनुभव और समाधान साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, Prevention Web के माध्यम से UNDRR तथा NESCAP के अंतर्गत एशिया एवं प्रशांत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र (APCTT) जैसे प्लेटफॉर्म DRR और जलवायु प्रौद्योगिकियों से संबंधित वैश्विक ज्ञान साझा करने को प्रोत्साहित करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, SAMEEKSHA, TERI KMS, KxSD तथा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जैसे प्लेटफॉर्म नवाचार, सतत विकास, ऊर्जा दक्षता और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देते हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) में संस्थागत ज्ञान विनिमय की परिकल्पना पहले से ही आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भारतीय विश्वविद्यालय एवं संस्थान नेटवर्क (IUINDRR) जैसी पहलों के माध्यम से साकार हो रही हैं, जिसके सदस्यों में IITs, IIMs, NITs, IIRS और केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित लगभग 352 संस्थान और विश्वविद्यालय शामिल हैं। यह प्लेटफॉर्म विश्वविद्यालयों के साथ जुड़कर आपदा जोखिम न्यूनीकरण में अनुसंधान और शिक्षण को बढ़ावा देता है। यह पीएचडी की पढ़ाई को प्रोत्साहित करके, शोध परियोजनाओं के लिए फंडिंग देकर, और अच्छे शोध-पत्रों व अकादमिक कार्यों को मान्यता देकर छात्रों और शोधकर्ताओं की मदद करता है।

यह संस्थान विश्वविद्यालयों, विशेषज्ञों और पेशेवरों को एक साथ लाने में भी मदद करता है, जिससे कि वे ज्ञान साझा कर सकें और आपदा जोखिम को कम करने के लिए व्यावहारिक समाधान विकसित कर सकें। यह विश्व के उन चुनिंदा नेटवर्कों में से एक है, जो राष्ट्रीय अकादमिक जगत को क्षमता निर्माण, नवाचार और नीतिगत निर्णय लेने में मदद करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिससे वे मिलकर आपदाओं के प्रभाव को कम और न्यूनतम कर सकें। निस्संदेह, IUINDRR एक ऐसी नींव प्रदान करता है, जिस पर एक अधिक व्यवस्थित और विस्तृत 'कम्युनिटी ऑफ़ प्रैक्टिस' (CoP) ढांचा विकसित किया जा सकता है। यह नेटवर्क शिक्षा प्रणाली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्यधारा में लाने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है, जिससे कि एक अधिक सुदृढ और आपदा-रोधी राष्ट्र का निर्माण किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, ऐसे प्लेटफॉर्म का विस्तार आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रयासों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक अवसर प्रदान करता है। पहला, यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के भीतर उपलब्ध विविध विशेषज्ञताओं, जैसे शासन एवं समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण, सीबीआरएन, सुदृढ बुनियादी ढांचा, समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन का व्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों, नीतिगत चर्चाओं और क्षेत्रीय नवाचारों के माध्यम से इस ज्ञान को निरंतर साझा, परिष्कृत और व्यावहारिक संदर्भों में लागू किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण ज्ञान साझा करने और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में व्यावहारिक अनुप्रयोगों के माध्यम से क्षमता निर्माण को मजबूत करके NIDM के मूल उद्देश्य को और अधिक मजबूती प्रदान करता है।

दूसरा, यह नीतिगत संवाद को प्रोत्साहित करता है। जब नीति-निर्माता, शोधकर्ता, नवोन्मेषक और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक मंच पर आते हैं, तो लू से निपटने की तैयारी, चक्रवात, बर्फाला तूफान या शहरी जोखिम मानचित्रण जैसे वास्तविक समय के मुद्दों पर CoP प्लेटफॉर्म के सदस्यों के अनुभवों के आधार पर चर्चा की जा सकती है। उदाहरण के लिए, NDMA के 'कम्युनिटी ऑफ़ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन' (CoDRR) ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आपदा जोखिम के विभिन्न विषयों, जैसे जंगल की आग और GLOF (हिमनदीय झील के फटने से उत्पन्न बाढ़) के जोखिम को कम करने पर चर्चाओं का आयोजन किया है; इन चर्चाओं में नेपाल, भूटान, कजाकिस्तान, पेरू और स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों के अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भी भाग लिया और अपने सर्वोत्तम अनुभवों को साझा किया। इन चर्चाओं से आपदाओं के शमन के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर नीतिगत दिशा-निर्देशों के निर्माण और रणनीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

तीसरा, CoP प्लेटफॉर्म आपदा प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण अनुसंधान की कमियों को दूर करने में सहायक होते हैं, जहाँ शोध अक्सर शोधकर्ताओं, प्रैक्टिशनरों और आपदा विशेषज्ञों के बीच सीमित संवाद, संरचित तंत्र की कमी तथा निष्कर्षों को व्यावहारिक समाधानों में परिवर्तित करने की तकनीकी जटिलताओं के कारण केवल अकादमिक परिणामों तक ही सीमित रह जाता है। इस संदर्भ में, CoP मंच उभरते जोखिम पैटर्न की पहचान करने, वास्तविक अनुभवों का दस्तावेजीकरण करने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग, बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने के लिए एक व्यावहारिक अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य कर सकता है, जिसे लक्षित अध्ययनों, नीतिगत संक्षिप्त विवरणों और प्रायोगिक हस्तक्षेपों में परिवर्तित किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, CoPs संस्थागत क्षमता निर्माण को मजबूत करता है। उदाहरण के लिए, इस प्लेटफॉर्म पर होने वाली चर्चाओं के माध्यम से तैयार किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम, वेबिनार, विषयगत परामर्श और प्रशिक्षण मॉड्यूल जैसे ज्ञान-उत्पादों को NIDM के मौजूदा क्षमता-निर्माण नेटवर्क के माध्यम से और बेहतर बनाया जा सकता है। इससे व्यापक दर्शकों तक पहुँच और ज्ञान साझा करने का दायरा बढ़ता है, साथ ही शैक्षणिक गुणवत्ता भी बनी रहती है और यह सुनिश्चित होता है कि प्रसारित की गई जानकारी उपयोगी बनी रहे।

इस प्रकार, एक सुव्यवस्थित 'कम्युनिटी ऑफ़ प्रैक्टिस' (CoP) प्लेटफॉर्म देशों, राज्यों और जिलों के बीच ज्ञान साझा करने में मदद करता है, जिससे हितधारकों को एक-दूसरे से सीखने और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को अपनाने में सहायता मिलती है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपदा से जुड़े कई जोखिमों की प्रकृति सीमाओं से परे होती है। उदाहरण के लिए, पराली जलाने से होने वाला वायु प्रदूषण न केवल पंजाब को प्रभावित करता है, बल्कि हवा के बहाव के कारण दिल्ली और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ-साथ पड़ोसी देशों को भी प्रभावित करता है।

भविष्य को देखते हुए, IUINDRR जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से NIDM में CoP को और सशक्त करने से क्षमता निर्माण, नीति अनुसंधान और ज्ञान साझा करने में इसकी भूमिका को मजबूती मिलेगी। संकाय विशेषज्ञता को बढ़ाकर, अनुसंधान को प्रोत्साहित करके और हितधारकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके, यह प्लेटफॉर्म केवल जानकारी प्रसारित करने से आगे बढ़कर निर्णयों को आकार देने, नीतियों को प्रभावित करने और जमीनी स्तर पर वास्तविक प्रतिरोधक क्षमता के निर्माण के लिए व्यावहारिक कदम उठाने में सक्षम हो सकता है।

## समुत्थानशीलता के वैश्विक अग्रदूतों का निर्माण: NIDM में आपदा जोखिम प्रबंधन पर ITEC प्रशिक्षण का समापन

डॉ. श्वेता रानी,  
परामर्शदाता, एनआईडीएम

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रतिष्ठित भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम के अंतर्गत आपदा जोखिम प्रबंधन पर 13वें समग्र पाठ्यक्रम (CCDRM) का सफलतापूर्वक समापन किया। इस कार्यक्रम का समन्वयन श्री शेखर चतुर्वेदी, सहायक प्राध्यापक, NIDM द्वारा किया गया, जबकि सह-समन्वयन डॉ. सुषमा गुलेरिया, सह-प्राध्यापक, NIDM एवं सुश्री नाज़िया खान, IPRO, NIDM द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम NIDM के कार्यकारी निदेशक, श्री मधुप व्यास, भा.प्र.से. के दूरदर्शी मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में इथियोपिया, फिजी, केन्या, लेबनान, म्यांमार, नामीबिया, मंगोलिया, युगांडा, मिस्र और भूटान से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह एक गहन क्षमता निर्माण कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में ज्ञान, कौशल और वैश्विक सहयोग को मजबूत करना था।



इस प्रशिक्षण कार्यक्रम ने आपदा जोखिम शासन, नीतिगत ढांचे और व्यावहारिक प्रतिक्रिया तंत्र की व्यापक समझ प्रदान की। प्रतिष्ठित संकाय सदस्यों और विशेषज्ञों द्वारा संचालित सत्रों में भारत में आपदा प्रबंधन की आधारभूत अवधारणाएं, आपदा शासन के संस्थागत तंत्र, जोखिम की संवेदनशीलता एवं क्षमता आकलन, घटना प्रतिक्रिया प्रणाली, जलवायु समुत्थानशीलता तथा शहरी बाढ़ के खतरों को कम करने जैसे प्रमुख विषयों को शामिल किया गया।

प्रतिभागियों ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडर्ड फ्रेमवर्क और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) पर चर्चा के माध्यम से आपदा जोखिम को कम करने के प्रति भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं को भी समझा। इन सत्रों के द्वारा प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए वैश्विक प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय और स्थानीय कार्यों के साथ एकीकृत करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

इस कार्यक्रम की एक विशेषता इसका सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव का समन्वय था। प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के विशेषज्ञों के साथ बातचीत की और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) जैसे प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों का दौरा किया, जहाँ उन्हें उन्नत निगरानी तकनीकों और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हुई। कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) का दौरा था, जहाँ प्रतिभागियों ने खोज एवं बचाव अभियानों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन देखा।

शैक्षणिक गतिविधियों के अतिरिक्त, इस कार्यक्रम ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान और अंतरराष्ट्रीय मित्रता को भी मजबूत किया। प्रतिभागियों ने राष्ट्रपति भवन और अमृत उद्यान जैसे प्रतिष्ठित स्थलों के साथ-साथ दिल्ली और आगरा के ऐतिहासिक स्थलों का भी दौरा किया और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को करीब से जाना। सांस्कृतिक संध्या ने प्रतिभागियों के बीच आपसी संबंधों को और भी मजबूत किया, जिसमें संगीत, प्रस्तुतियां और साझा परंपराओं के माध्यम से विविधता का उत्सव मनाया गया।

इस कार्यक्रम का समापन संयुक्त राष्ट्र महासचिव के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विशेष प्रतिनिधि एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNDRR) के प्रमुख, श्री कमल किशोर के प्रेरणादायक वीडियो संदेश के साथ हुआ। अपने संबोधन में, उन्होंने आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हो रही चुनौतियों से निपटने में वैश्विक सहयोग, ज्ञान के आदान-प्रदान और संयुक्त प्रयास के महत्व को रेखांकित किया और दुनिया भर में सशक्त समुदायों के निर्माण के लिए मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

# प्रशिक्षणार्थियों के अनुभव

## आपदा जोखिम प्रबंधन पर 11वें व्यापक पाठ्यक्रम के प्रतिभागी



**नाम:** सुश्री काकली साहा

**पदनाम:** टीसीएस, उप-मंडल दंडाधिकारी, शांतिबाजार, दक्षिण त्रिपुरा

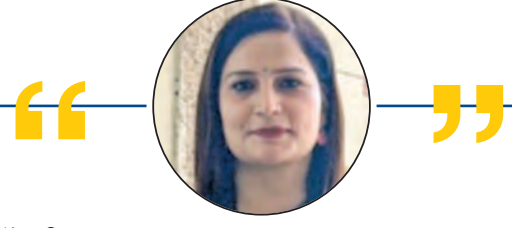
पूर्वोत्तर के एक प्रतिभागी और त्रिपुरा के प्रशासक के दृष्टिकोण से, NIDM दिल्ली का इन-हाउस आपदा जोखिम प्रबंधन प्रशिक्षण व्यापक और सुव्यवस्थित था। चांदनी चौक HRVC विश्लेषण ने शहरी खतरों के प्रति मेरे विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को और मजबूत किया। NDRF, IMD, NSC और रिमोट सेंसिंग- ISRO से मिले इनपुट्स ने प्रभावी प्रतिक्रिया समन्वय और वैज्ञानिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।



**नाम:** डॉ. रामकृष्णन आर.

**पदनाम:** वैज्ञानिक-सी  
केन्द्रीय राज्य वन सेवा अकादमी, कोयंबटूर

NIDM में आपदा जोखिम प्रबंधन पर आयोजित 11वाँ व्यापक पाठ्यक्रम एक अत्यंत ज्ञानवर्धक और पेशेवर रूप से तैयार किया गया कार्यक्रम था। इसके सुव्यवस्थित मॉड्यूल, विशेषज्ञों के नेतृत्व वाले सत्र और IMD तथा NDRF जैसे संस्थानों के क्षेत्रीय दौरे ने मुझे बहुमूल्य व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया। प्रौद्योगिकी, जोखिम मूल्यांकन उपकरणों और विभिन्न क्षेत्रों के दृष्टिकोणों के समावेश ने विभिन्न प्रकार के खतरा और जोखिमों के प्रबंधन के प्रति मेरी समझ को और अधिक सके माहौल ने इस कार्यक्रम को अंतर्दृष्टिपूर्ण होने के साथ-साथ अत्यंत प्रभावशाली बना दिया।



**नाम:** डॉ. रुचिका डबास

**पदनाम:** सहायक प्राध्यापक, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, SRM विश्वविद्यालय

मुझे NIDM द्वारा आयोजित कोर्स के बारे में अपनी राय साझा करते हुए खुशी हो रही है। यह कोर्स बहुत ही जानकारीपूर्ण और अच्छी तरह से व्यवस्थित था। इसने आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के बारे में गहरी जानकारी दी और तैयारी, शमन, प्रतिक्रिया और रिकवरी की रणनीतियों के बारे में मेरी समझ को और बेहतर बनाया।

इस कार्यक्रम के माध्यम से, मैंने कई नई अवधारणाएँ, व्यावहारिक दृष्टिकोण और वास्तविक जीवन के केस स्टडी सीखे, जिससे आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मेरा ज्ञान और बढ़ा। सत्र बहुत ही दिलचस्प थे, और Resource persons बहुत ही जानकार और सहयोगी थे।

कुल मिलाकर, यह एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव था, और मैं इस मूल्यवान कोर्स का हिस्सा बनने का अवसर मिलने के लिए आभारी हूँ। इसने मेरे शैक्षणिक और पेशेवर व्यक्तित्व के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है।



**नाम:** श्री राघवेंद्र सिंह

**पदनाम:** जूनियर रिसर्च कंसल्टेंट,  
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत सरकार

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 11वें व्यापक कोर्स ने भारत के DRR फ्रेमवर्क, आपदा प्रबंधन चक्र और विभिन्न एजेंसियों की भूमिकाओं के बारे में मजबूत वैचारिक स्पष्टता प्रदान की। व्यावहारिक अनुभव, पूरे भारत से आए विविध प्रतिभागी और बेहतरीन सत्रों ने सीखने के अनुभव को और भी बेहतर बनाया। यह कोर्स मानवाधिकार, पर्यावरण और आपदा-संबंधी कार्यों के क्षेत्र में मेरे काम के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं।

# प्रशिक्षणार्थियों के अनुभव

## आपदा जोखिम प्रबंधन पर 12वें व्यापक पाठ्यक्रम के प्रतिभागी



“

”

**नाम:** सुश्री सुनाली रानी

**पदनाम:** तहसीलदार, एफसीआर, जम्मू एवं कश्मीर

जम्मू जैसे क्षेत्र में कार्य करते हुए, जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ और मौसम अक्सर गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं, यह पाठ्यक्रम अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। इसने जमीनी स्तर पर आपदा तैयारी, प्रारंभिक प्रतिक्रिया तंत्र तथा विभागों के बीच समन्वय की स्पष्ट समझ प्रदान की, जो प्रभावी फील्ड प्रशासन के लिए अत्यंत आवश्यक है।

इन सत्रों का व्यावहारिक स्वरूप और वास्तविक जीवन के मामलों पर आधारित चर्चाओं ने इसे विशेष रूप से उन अधिकारियों के लिए प्रासंगिक बना दिया, जो बदलते जोखिम परिदृश्यों से जूझ रहे हैं। इस कार्यक्रम से मिली सीख निश्चित रूप से मेरे कार्यक्षेत्र में अधिक प्रभावी योजना निर्माण और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में सहायक होगी।



“

”

**नाम:** डॉ. अंजलि यादव

**पदनाम:** प्राध्यापक, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के तौर पर, मुझे आपदा जोखिम प्रबंधन पर आधारित व्यापक पाठ्यक्रम (CCDRM) अत्यंत समृद्ध और ज्ञानवर्धक लगा। इस कोर्स की संरचना बेहद सुव्यवस्थित थी, विशेष रूप से जोखिम आकलन, HRVC विश्लेषण तथा नीतिगत ढाँचों के क्षेत्रों में, जिसमें सैद्धांतिक अवधारणाओं और व्यावहारिक अनुप्रयोगों का संतुलित मिश्रण प्रस्तुत किया गया था।

इसमें आयोजित इंटरैक्टिव सत्रों और विशेषज्ञों द्वारा संचालित चर्चाओं ने सीखने के अनुभव को अत्यंत रोचक और प्रभावशाली बना दिया। इस कार्यक्रम ने मेरे अकादमिक दृष्टिकोण को काफी समृद्ध किया, और मैं इस कोर्स से प्राप्त ज्ञान को अपने अध्यापन एवं संस्थागत कार्यप्रणालियों में समाहित करने के लिए उत्सुक हूँ।

## आपदा जोखिम प्रबंधन पर 13वें व्यापक पाठ्यक्रम के प्रतिभागी



“

”

**नाम:** श्री कुपी

**पदनाम:** निदेशक, आपदा प्रबंधन एवं शांति निर्माण, केन्या

NIDM आपदा शासन और क्षमता विकास के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान के रूप में अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ के व्याख्यानों की गहराई, विभिन्न प्रकार के आपदाओं से निपटने का व्यवस्थित दृष्टिकोण, और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, पूर्व-अनुमानित कार्रवाई ढाँचों, घटना कमान प्रणालियों तथा 'बेहतर पुनर्निर्माण' (Build Back Better) रणनीतियों का व्यावहारिक अनुभव—ये सभी बातें एक ऐसे अत्यंत सुसज्जित और दूरदर्शी संस्थान को दर्शाती हैं, जो वैश्विक आपदा प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मैं NIDM की उस असाधारण टीम के प्रति अपनी हार्दिक सराहना व्यक्त करता हूँ, जिनके पेशेवर रवैये और समर्पण ने इस अनुभव को अत्यंत प्रभावशाली और परिवर्तनकारी बना दिया। शेखर चतुर्वेदी, नाज़िया खान, विशाल काटेकर, अमनदीप, राहुल, और पूरी समन्वय तथा संकाय टीम का विशेष आधार; उनके ज्ञानवर्धक सत्रों, त्रुटिरहित व्यवस्था और बौद्धिक गंभीरता ने हमारे आपदा प्रबंधन ज्ञान को और भी अधिक समृद्ध किया।

मैं केन्या स्थित भारतीय उच्चायोग के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस अवसर को सुलभ बनाने में सहायता की और क्षमता निर्माण के माध्यम से हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग को और अधिक सुदृढ़ किया।

यह न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि केन्या के लिए एक रणनीतिक लाभ भी है। यहाँ से अर्जित ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हमारे राष्ट्रीय और काउंटी-स्तरीय आपदा प्रबंधन तंत्रों के भीतर संस्थागत समन्वय, पूर्व-अनुमानित कार्रवाई, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के एकीकरण और आपदा-रोधी संबंधी नियोजन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

इस अनुभव के लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ, और अब मैं इस सीख को व्यावहारिक कार्यों में परिणत करने के लिए पूरी तरह तत्पर हूँ।

# प्रशिक्षणार्थियों के अनुभव

## आपदा जोखिम प्रबंधन पर 13वें व्यापक पाठ्यक्रम के प्रतिभागी



**नाम:** मोहम्मद ई.

**पदनाम:** वित्तीय एवं प्रशासनिक शोधकर्ता, विदेश मंत्रालय, मिस्र

मैं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रति अपनी सराहना व्यक्त करना चाहता हूँ। यह मेरे लिए एक गहन और प्रेरणादायक अनुभव रहा। प्रशिक्षक अत्यंत ज्ञानवान थे और उन्होंने अपनी विशेषज्ञता के साथ-साथ व्यावहारिक अनुभव भी उदारता से साझा किए। प्रतिभागियों की विविधता ने भी सीखने का एक समृद्ध माहौल बनाया, जहाँ हम एक-दूसरे के साथ अपने विचार साझा कर सके और एक-दूसरे से सीख सके। आयोजकों ने इस प्रशिक्षण को बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से संचालित किया।

इस कोर्स को जो बात सचमुच अनोखी बनाती है, वह है इसका सिद्धांत और वास्तविक अभ्यास का मेल। क्लासरूम सेशन के अलावा, हमें संबंधित अधिकारियों और संस्थानों का दौरा करने का भी अवसर मिला, जिससे हमारी जानकारी कहीं ज्यादा सार्थक और ठोस हो गया। मेरे लिए सबसे कीमती सबकों में से एक यह समझना था कि आपदा प्रबंधन का मतलब सिर्फ आपात स्थितियों पर प्रतिक्रिया देना ही नहीं है, बल्कि आपदाएँ आने से पहले तैयारी करना, जोखिम का आकलन करना और कमियों को दूर करना भी है। यह दृष्टिकोण आपदाओं के बारे में हमारी सोच को बदल देता है, जिसमें संकटों पर प्रतिक्रिया देने की बजाय प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय रूप से विकसित करना है।

पेशेवर तौर पर, इस ट्रेनिंग ने आपदा जोखिम प्रबंधन के बारे में मेरी समझ को मज़बूत किया और मुझे ऐसी व्यावहारिक अंतर्दृष्टि दी, जिसे मैं अपने काम और अपने अकादमिक शोध कार्यों में भी लागू कर सकता हूँ। ज्ञान और कौशल से परे, इस ट्रेनिंग ने पेशेवरों का एक मूल्यवान नेटवर्क तैयार किया, जो सुरक्षित और ज्यादा सशक्त समाज बनाने के साझा संकल्प से जुड़े थे। मैंने जो कुछ भी सीखा है, उसे लागू करने और हमारे देशों के बीच सहयोग को मज़बूत करने के लिए उत्सुक हूँ।



**नाम:** खिन न्येन शु

**पदनाम:** उप निदेशक, राजकोष विभाग, वित्त एवं राजस्व मंत्रालय (MOFR), म्यांमार

मैं सुश्री खिन न्येन शु हूँ, म्यांमार में वित्त और राजस्व मंत्रालय के अंतर्गत ट्रेजरी विभाग में उप निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने 16.2.2026 से 27.2.2026 तक भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में 'समग्र आपदा जोखिम प्रबंधन पाठ्यक्रम' में भाग लिया। इस पाठ्यक्रम के दौरान हुई चर्चाओं और दिए गए व्याख्यानों के आधार पर, हमें भारत की प्रभावी और उन्नत आपदा प्रबंधन पद्धतियों के बारे में जानने का अवसर मिला।

इससे हमें अपने देश में लागू की जा रही आपदा प्रबंधन गतिविधियों को समझने में भी मदद मिली। इसके अतिरिक्त, इस पाठ्यक्रम ने हमें यह उपयोगी जानकारी भी प्रदान की कि प्राकृतिक आपदाएँ आने पर होने वाले संभावित नुकसान और क्षति का अनुमान कैसे लगाया जाए, तथा रोकथाम और पूर्व-तैयारी के लिए किन तरीकों का उपयोग किया जा सकता है।

अतः, इस पाठ्यक्रम से प्राप्त ज्ञान अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है, और इसके माध्यम से ऐसे उपयोगी दृष्टिकोण प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हमारे देश के हित के लिए भी लागू किया जा सकता है।



**नाम:** ई खिंग मिंग

**पदनाम:** स्टाफ अधिकारी, निर्माण मंत्रालय, म्यांमार

मैं मेहमाननवाजी, सहानुभूति, जवाबदेही, लचीले रवैये, रहने की आरामदायक व्यवस्था और स्वादिष्ट व ताज़ा भोजन के लिए भारत में NIDM के सभी सदस्यों की सचमुच आभारी हूँ, जिसमें दूध, तरह-तरह के फल, अलग-अलग तरह के जूस और अन्य पारंपरिक नाश्ते शामिल थे। भारत में मेरी सबसे यादगार यात्राएँ इंडिया गेट, लाल किला, दिल्ली हाट (INA), ताजमहल (आगरा) और राष्ट्रपति भवन की रही। हालाँकि लेक्चर देने वालों के लिए कुछ चुनौतियाँ थीं, फिर भी मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हमें भारत के कुछ स्थानों पर फूलों की खरीदारी करने का मौका दिया। इसके अलावा, मुझे NIDM से ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए 'आपदा जोखिम प्रबंधन' के अपने आगे के अध्ययन के लिए बहुमूल्य जानकारी मिली; यह तब काम आएगी जब मुझे आपदा जोखिम प्रबंधन पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। अगर मुझे NIDM में पढ़ने का अवसर मिलता है, विशेष रूप से 'जलवायु परिवर्तन' या 'आपदा जोखिम प्रबंधन' में अपनी PhD की डिग्री के लिए, और वह भी पूरी तरह से फंडेड स्कॉलरशिप के साथ तो मुझे बहुत खुशी होगी। NIDM के सभी सदस्यों के गर्मजोशी भरे व्यवहार और धैर्य के कारण, NIDM में अपना दो हफ्ते का लंबा ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा करने के बाद, यह सपना अब सच होता दिख रहा है। इन दो हफ्तों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, कश्मीर से और अन्य अलग-अलग देशों से मेरे दोस्त बने। मेरे लिए यह एक शानदार नेटवर्क साबित हुआ है, और मैं इस अनुभव को कभी नहीं भूल पाऊँगी। NDRF के दौरों ने मुझे भावनात्मक रूप से बहुत प्रभावित किया; मुझे यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि भारत की NDRF ने म्यांमार के मांडले में आए भूकंप के दौरान किस तरह मदद और सहयोग दिया था। मैं NDRF के सभी सदस्यों को बार-बार सलाम करते हुए अपना सम्मान व्यक्त करना चाहूँगी। मुझे जलवायु परिवर्तन से संबंधित बहुमूल्य ज्ञान मिला, जिसमें मापने की प्रणालियाँ, सैटेलाइट और अन्य मापक यंत्र शामिल थे। दुनिया भर के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा या सबसे अहम विषय 'आपदा जोखिम प्रबंधन' ही है। हालाँकि भारत में पढ़ाई से जुड़ी मेरी बहुत सी अविस्मरणीय यादें हैं, फिर भी मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहूँगी। अंत में, मैं सभी भारतीय लोगों के लिए यह प्रार्थना करना चाहूँगी कि वे हमेशा खुश, स्वस्थ और समृद्ध रहें।

# प्रशिक्षणार्थियों के अनुभव

## आपदा जोखिम प्रबंधन पर 13वें व्यापक पाठ्यक्रम के प्रतिभागी



“

”

**नाम:** मोज़ेस आँडी

**पदनाम:** वरिष्ठ विधायी एवं नीति अधिकारी, सियाया काउंटी सरकार, केन्या

यह कोर्स बहुत ही ज्ञानवर्धक और व्यावहारिक था। मुझे आपदा जोखिम की तैयारी के बारे में न केवल उन जाने-माने विशेषज्ञों से बहुमूल्य जानकारी और सुझाव मिले, जिन्होंने सत्रों का संचालन किया, बल्कि साथी प्रतिभागियों के साथ सार्थक बातचीत के माध्यम से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और भारतीय मौसम विभाग (IMD) के फ़ील्ड स्टडी विशेष रूप से ज्ञानवर्धक रहे, क्योंकि उन्होंने आपदा की तैयारी, प्रतिक्रिया प्रणालियों और प्रारंभिक चेतावनी तंत्रों पर वास्तविक दुनिया का नज़रिया प्रदान किया।

इस प्रशिक्षण के माध्यम से, मैंने आपदा-पूर्व तैयारी और आपदा-पश्चात पुनर्प्राप्ति योजना, दोनों के बारे में अपनी समझ को मज़बूत किया है। अपनी 'बैक-होम एक्शन प्लान' (घर लौटने के बाद की कार्ययोजना) में, मेरा इरादा आपदा आने से पहले आपदा जोखिम की तैयारी के लिए प्रभावी रणनीतियों की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना है, साथ ही आपदा आने के बाद पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाओं को भी मज़बूत करना है।

परिणामस्वरूप, मैं प्रमुख हितधारकों के साथ मिलकर केन्या के सियाया काउंटी में सियाया, बोंडो और उगुंजा की नगरपालिकाओं के भीतर अचानक आने वाली बाढ़ (फ्लैश फ्लड) की चपेट में आने वाले क्षेत्रों की पहचान करने की योजना बना रहा हूँ। यह पहल स्थानीय तैयारी को बेहतर बनाने में मदद करेगी और जोखिम कम करने के लिए सोच-समझकर निर्णय लेने में मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

मेरा व्यापक लक्ष्य हमारी नगरपालिकाओं की दीर्घकालिक योजना और विकास में योगदान देना है, जिससे कि वे स्मार्ट और सुदृढ़ शहरों में तब्दील हो सकें। इसके अंतर्गत, आपदा जोखिम प्रबंधन को मज़बूत बनाने और हमारी स्थानीय सरकार के भीतर आपदा प्रबंधन कार्यों को विनियमित करने के लिए प्रासंगिक नीतियाँ तैयार करना, तथा मौजूदा 'सियाया काउंटी आपदा प्रबंधन अधिनियम (2015)' में संशोधन प्रस्तावित करना शामिल होगा, जिसका लाभ वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को मिल सके।

मैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) और सभी सहयोगी हितधारकों का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, और मुझे ऐसे ज्ञान तथा व्यावहारिक कौशलों से सुसज्जित किया, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण और सुदृढ़ता निर्माण के वैश्विक प्रयासों में अपना योगदान देंगे।



“

”

**नाम:** अम्मोन मविया माबुकु

**पदनाम:** अग्नि एवं बचाव अधिकारी, नामीबिया हवाई अड्डा कंपनी, नामीबिया

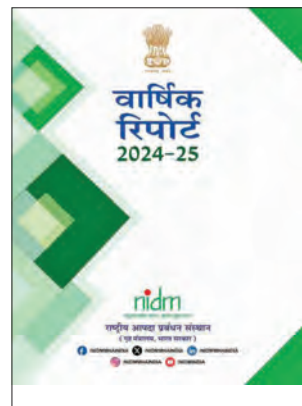
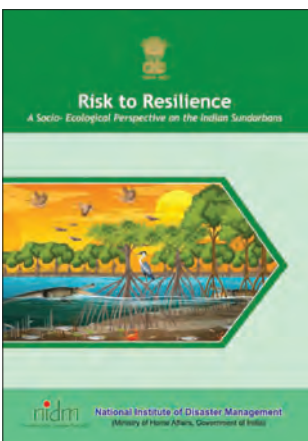
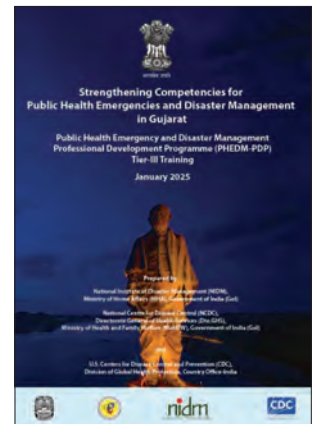
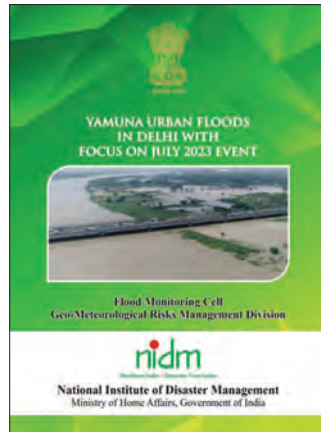
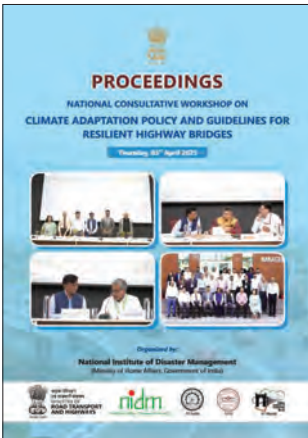
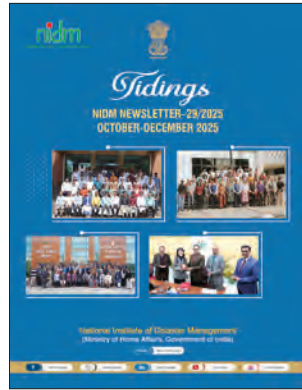
नामीबिया एयरपोर्ट्स कंपनी की ओर से, मैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे 'व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन पाठ्यक्रम' में हिस्सा लेने का मौका दिया।

यह पाठ्यक्रम बहुत ही जानकारीपूर्ण और ज्ञानवर्धक था; इसने आपदा की तैयारी, जोखिम कम करने, राहत कार्यों में तालमेल बिठाने और आपदा झेलने की क्षमता बढ़ाने के बारे में बहुमूल्य जानकारी और व्यावहारिक जानकारी प्रदान की। यह प्रशिक्षण बहुत ही व्यवस्थित ढंग से आयोजित किया गया था और इसे ऐसे जानकार विशेषज्ञों ने संचालित किया, जिन्होंने सैद्धांतिक पहलुओं और व्यावहारिक अनुभवों, दोनों को ही बहुत प्रभावी ढंग से साझा किया।

होसेया कुटाको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक 'अग्नि एवं बचाव अधिकारी' के तौर पर, इस कार्यक्रम से प्राप्त ज्ञान और कौशल हमारे संगठन के भीतर आपदा जोखिम प्रबंधन की प्रक्रियाओं को मज़बूत बनाने में, और आपातकालीन स्थितियों में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने की हमारी क्षमता को बढ़ाने में, बहुत बड़ा योगदान देंगे।

कुल मिलाकर, यह पाठ्यक्रम सीखने का एक बेहतरीन अनुभव था, और मैं विभिन्न संस्थानों में क्षमता निर्माण करने तथा आपदा जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा देने के प्रति NIDM की प्रतिबद्धता की सचमुच सराहना करता हूँ।

# एनआईडीएम प्रकाशन



## एनआईडीएम पोर्टल्स



वर्ष 2025-26 के दौरान एनआईडीएम द्वारा आयोजित एवं प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी के लिए कृपया नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें।



### National Institute of Disaster Management

Ministry of Home Affairs, Government of India

**"STAY CONNECTED, STAY INFORMED" - FOLLOW US**

SCAN ME 

 LINKEDIN NIDMMHA	 FACEBOOK NIDMMHAINDIA	 X NIDMMHAINDIA	 INSTAGRAM NIDMMHAINDIA	 YOUTUBE NIDMINDIA
---	--	---	---	--





nidm

Resilient India - Disaster free India

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान  
(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

प्लॉट नं. 15, पॉकेट 3, ब्लॉक बी, सेक्टर-29, रोहिणी, दिल्ली-110042  
वेबसाइट : <https://nidm.gov.in>